UPSC-CSE 2027/28

DAILY CURRENT AFFAIRS

ONE STOP SOLUTION

By **Faiyaz Sir**



The Indian EXPRESS

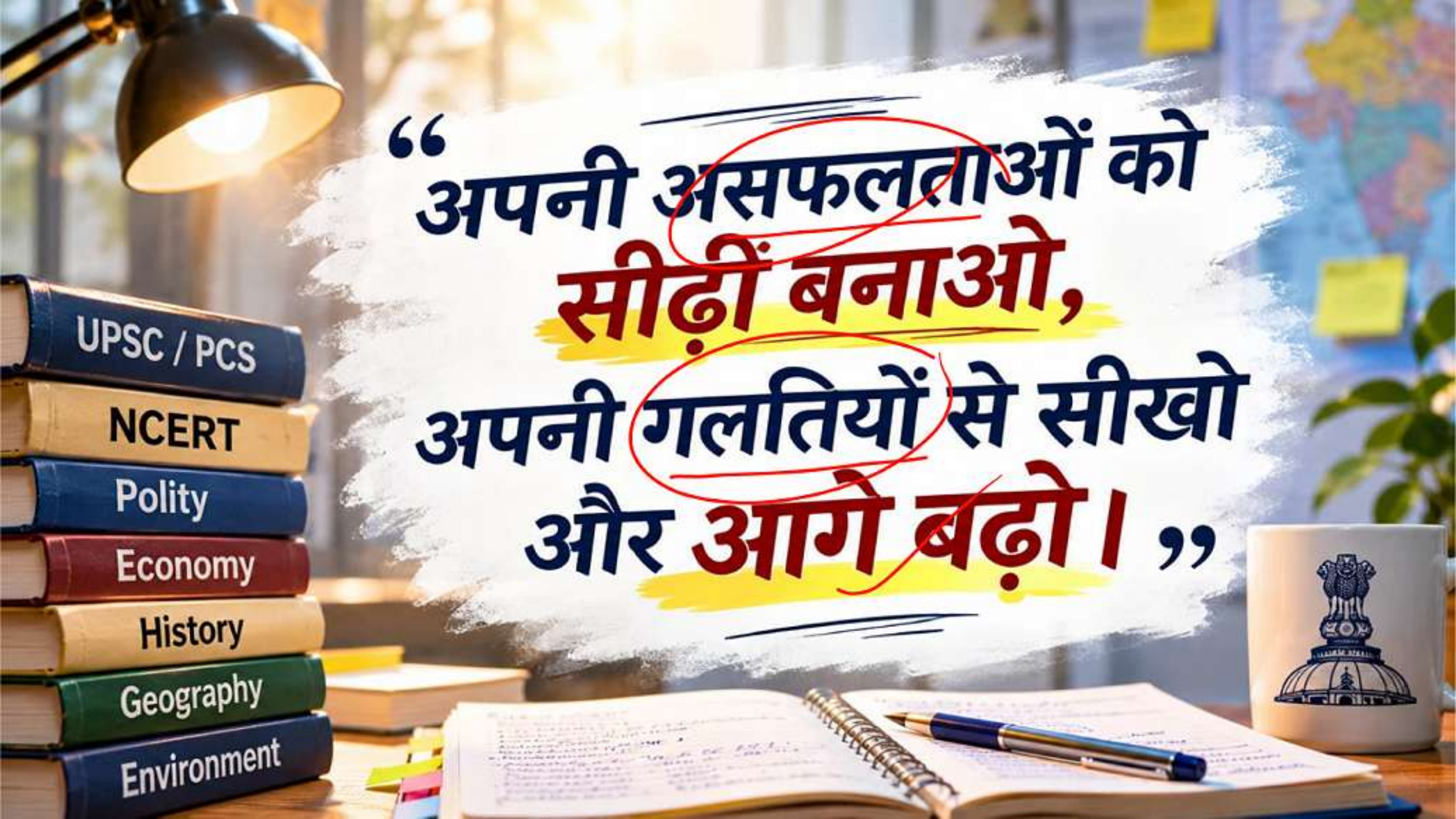
THE HINDU

pib PRESS INFORMATION BUREAU

02 NOVEMBER

COMPLETE COVERAGE | EXAM FOCUSED | ANALYSIS MADE EASY | STATIC + CURRENT INTEGRATION

STAY AHEAD STAY PREPARED


“अपनी असफलताओं को
सीढ़ीं बनाओ,
अपनी गलतियों से सीखो
और आगे बढ़ो।”
UPSC / PCS
NCERT
Polity
Economy
History
Geography
Environment

आज क्या पढ़ेंगे?

- Social Security Coverage
- GSLV-F18/NVS03
- Binance Hacking
- El-Nino
- Unemployment – PLFS
- ECI-Protest
- GST Collection
- Cyclone Murasu
- 10th Schedules
- TN Day
- Project 18A
- US-Quba-UN
- Bhutan – India – GMC Project
- Iran – USA
- Hylo Open Super 500 Badminton Tournament
- Commonwealth Kabaddi Championship
- INS Trisul
- BRESE 2026
- Air Force Chief

Result Mitra

पत्र सूचना कार्यालय
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

Economy

भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज

कार्यबल सुरक्षा को मजबूती

Posted On: 31 OCT 2026 9:30AM

व्यापक ईपीएफओ कवरेज, डिजिटल सुधारों और कल्याणकारी पहलों के माध्यम से भारत के सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार हुआ है। ईपीएफओ पात्र सदस्यों को भविष्य निधि बचत, पेंशन और बीमा लाभ प्रदान करता है। अनिवार्य कवरेज वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों के इसके दायरे में आने की उम्मीद है। डिजिटल पहल का उद्देश्य पंजीकरण, निकासी और दावों के निपटान को सरल बनाना है। ईपीएफओ के अलावा, ई-श्रम जैसी पहल और पीएम-एबीवाईएम और प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना जैसी योजनाएं असंगठित श्रमिकों और कमजोर समूहों को सहायता प्रदान करती हैं। ये उपाय रोजगार श्रेणियों और जीवन के चरणों में सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच को मजबूत करते हैं।

Result Mitra

श्रमिक सुरक्षा के एक स्तंभ के रूप में सामाजिक सुरक्षा

- जैसे-जैसे अर्थव्यवस्थाएं विकसित होती हैं, रोजगार पैटर्न और आजीविका के स्रोत बदलते रहते हैं। अनौपचारिक, गिग और प्लेटफ़ॉर्म-आधारित कार्य का विस्तार, आय और रोजगार निरंतरता में भिन्नता के साथ, श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा को तेजी से महत्वपूर्ण बनाता है। सामाजिक सुरक्षा जीवन के विभिन्न चरणों में आय की हानि और अन्य आकस्मिकताओं से सुरक्षा प्रदान करती है। यह सेवानिवृत्ति और आय संबंधी असुरक्षा की अवधि के दौरान वित्तीय सुरक्षा को भी मजबूत करता है।
- भारत ने हाल के वर्षों में सामाजिक सुरक्षा की पहुंच का काफी विस्तार किया है। **सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19 प्रतिशत से बढ़कर 2026 में 68.4 प्रतिशत हो गया।** इस विस्तार ने एक बिलियन से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा ढांचे के भीतर ला दिया है।
- भारतीय श्रमिकों के लिए, सामाजिक सुरक्षा उनके कामकाजी वर्षों से परे वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) पात्र श्रमिकों के लिए भविष्य निधि, पेंशन और बीमा योजनाओं को कार्यान्वित करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है और **दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संस्थानों में से एक** है। इसकी योजनाएं श्रमिकों को सेवानिवृत्ति बचत बनाने, पेंशन लाभ प्राप्त करने और उनके परिवारों के लिए सुरक्षित वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद करती हैं।

Result Mitra

ईपीएफओ-आधारित सामाजिक सुरक्षा के तीन स्तंभ

- ईपीएफओ सामाजिक सुरक्षा संरचना में भविष्य निधि बचत, पेंशन लाभ और बीमा सुरक्षा शामिल है।
- **कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026 (ईपीएफ)**
  सामाजिक सुरक्षा कोड, 2020 (कोड) के तहत शुरू किए गए नए ईपीएफ 2026 ने पूर्ववर्ती कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026 को बदल दिया। EPF 2026 सदस्यों को योगदान और अर्जित ब्याज के माध्यम से सेवानिवृत्ति बचत बनाने में सक्षम बनाता है। यह निर्धारित शर्तों के अधीन आवास, उच्च शिक्षा, विवाह और चिकित्सा उपचार सहित निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए आंशिक निकासी की भी अनुमति देता है।
- **कर्मचारी पेंशन योजना, 2026 (ईपीएस) कोड**
  के तहत नए ईपीएस 2026 ने पूर्ववर्ती कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 को बदल दिया। ईपीएस 2026 सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति या विकलांगता पर पात्र सदस्यों को मासिक पेंशन लाभ प्रदान करता है। यह मृत सदस्यों के पात्र आश्रितों को पेंशन लाभ भी प्रदान करता है, जिसमें पति-पत्नी, बच्चे और परिवार के अन्य पात्र सदस्य शामिल हैं।
- **कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना, 2026 (ईडीएलआई)**
  कोड के तहत नई ईडीएलआई 2026 ने पूर्ववर्ती कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना, 1976 को बदल दिया है और सेवा के दौरान मृत्यु की स्थिति में पात्र ईपीएफ सदस्यों को बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना सदस्यों को अलग से बीमा प्रीमियम का भुगतान करने की आवश्यकता के बिना 7 लाख रूपये तक का बीमा लाभ प्रदान करती है।

कार्यबल में ईपीएफओ कवरेज का विस्तार

- पिछले कुछ वर्षों में, ईपीएफओ ने भारत के बढ़ते औपचारिक कार्यबल के साथ-साथ अपनी पहुंच का विस्तार किया है। इसकी प्रगति व्यापक सदस्यता, संस्थागत कवरेज और पेंशन सहायता में परिलक्षित होती है।
- इस अवधि के दौरान ईपीएफओ की योगदान सदस्यता में काफी वृद्धि हुई है। **योगदान देने वाले सदस्यों की संख्या 2014-15 में 3.49 करोड़ से बढ़कर लगभग 7.98 करोड़ (16 सितंबर, 2026 तक) हो गई।** यह इस अवधि में लगभग **4.49 करोड़ योगदान देने वाले सदस्यों** की वृद्धि दर्शाता है।
- सितंबर 2026 तक, **7.68 लाख प्रतिष्ठान** ईपीएफओ में योगदान दे रहे हैं। यह पात्र श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने के लिए एक व्यापक संस्थागत आधार प्रदान करता है।



Result Mitra

- सदस्यता के साथ-साथ पेंशन सहायता का भी विस्तार हुआ है। **ईपीएफओ ने 2014-15 के दौरान 51.04 लाख पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान** किया। सितंबर 2026 तक लगभग **82 लाख पेंशनभोगियों** को पेंशन लाभ मिल रहा है। यह **31 लाख से अधिक पेंशनभोगियों** की वृद्धि दर्शाता है।
- सामाजिक सुरक्षा लाभों का पैमाना भी काफी बढ़ गया है। **2014-15 के दौरान 1.30 करोड़ दावों का निपटान किया गया**। पिछले एक वर्ष की अवधि (अक्टूबर, 2026 तक) में, ईपीएफओ ने **6.42 करोड़ दावों का निपटान किया**। यह ईपीएफओ सदस्यों और लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बढ़ते पैमाने को दर्शाता है।

डिजिटल और सेवा सुधारों के माध्यम से ईपीएफओ को मजबूती

- ईपीएफओ व्यापक कवरेज, सरलीकृत दावा निपटान और डिजिटलीकरण के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा वितरण को मजबूत कर रहा है। सुधार अनुपालन में सुधार, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को कम करने और भविष्य निधि और पेंशन सेवाओं तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं।



वेतन सीमा संशोधन

- **कवरेज का विस्तार**: अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के लिए वेतन सीमा को अंतिम बार सितंबर 2014 में 6,500 से 15,000 रूपए प्रति माह तक संशोधित किया गया था। **सितंबर 2026 में, प्रति माह 25,000 रूपए तक की वृद्धि को मंजूरी दी गई थी।** संशोधन से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों को अनिवार्य कवरेज प्रदान करने की उम्मीद है। यह वेतन स्तर में परिवर्तन और बीच की अवधि में औपचारिक रोजगार के विस्तार को दर्शाता है। संशोधित सीमा अनिवार्य कवरेज के लिए पात्र कर्मचारियों के पूल को व्यापक बनाती है, जो लागू वैधानिक प्रावधानों के अधीन है।

पीएफ निकासी को सुव्यवस्थित करना और दावों के निपटारे में तेजी

- **सरलीकृत आंशिक निकासी नियम**: ईपीएफओ ने **आंशिक निकासी को नियंत्रित करने वाले 13 प्रावधानों को तीन श्रेणियों में समेकित किया** है: अनिवार्य आवश्यकताएं, आवास की आवश्यकताएं और विशेष परिस्थितियां। अनिवार्य आवश्यकताएं बीमारी, शिक्षा और विवाह से संबंधित खर्चों को कवर करती हैं। यह वर्गीकरण निकासी ढांचे को सरल बनाता है, जिससे पात्र सदस्यों के लिए भविष्य निधि बचत तक आसान पहुंच की सुविधा मिलती है।
- **उदारीकृत निकासी सीमाएं**: कर्मचारी अपने कार्य वर्षों के दौरान विशिष्ट वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी पीएफ बचत से आंशिक निकासी कर सकते हैं। यह उन्हें संपूर्ण संचित शेष राशि को निकाले बिना बचत तक पहुंचने की अनुमति देता है।
- ईपीएफओ ने शिक्षा के लिए 10 और शादी के लिए 5 निकासी की अनुमति देकर **इन प्रावधानों को सरल बनाया है।** इससे पहले, दोनों उद्देश्यों ने 3 आंशिक निकासी की संयुक्त सीमा साझा की थी। अक्टूबर 2025 में पेश किया गया संशोधित ढांचा पात्र सदस्यों को अपने पीएफ बैलेंस का 75 प्रतिशत तक निकालने की अनुमति देता है। इसमें लागू शर्तों के अधीन कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान शामिल है। न्यूनतम सेवा आवश्यकता को 12 महीनों में मानकीकृत किया गया है।
- **स्वत: दावा निपटान**: ईपीएफओ ने पात्र अग्रिम दावों के लिए ऑटो-सेटलमेंट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रूपये कर दिया। यह मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना पात्र निकासी की तेजी से प्रक्रिया को सक्षम बनाता है।
- **सरलीकृत बैंक सत्यापन**: ईपीएफओ ने पात्र ऑनलाइन दावों के लिए चेक-लीफ इमेज या अटेस्टेड बैंक पासबुक अपलोड करने की आवश्यकता को हटा दिया। यह कागजी कार्रवाई को कम करता है और क्लेम प्रक्रिया को आसान बनाता है।

अनुपालन को मजबूती और कारोबारी सुगमता

- **विश्वास, 2026**: यह योजना **ईपीएफ और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 और सामाजिक सुरक्षा कोड, 2020 के तहत नुकसान या दंड से जुड़े पात्र विवादों के एकमुश्त निपटान** की सुविधा प्रदान करती है। यह मुकदमेबाजी को कम करता है और डिजिटल, समयबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करता है। इस योजना में चुनौतीपूर्ण क्षति या दंड आदेश, लंबित या आंशिक वसूली, अंतिम आदेशों की प्रतीक्षा में जारी नोटिस और ऐसे मामले शामिल हैं जहां नोटिस अभी तक जारी नहीं किए गए हैं।
- 14 जून, 2024 से पहले के योग्य डिफॉल्ट पर देरी अवधि के आधार पर 0.25 प्रतिशत, 0.50 प्रतिशत या 1 प्रतिशत की मासिक क्षति दर कम हो जाती है।
- नियोक्ताओं को लागू वैधानिक ब्याज का भुगतान करना चाहिए और निपटाए गए विवादों पर आगे की अपील नहीं करने का वचन देना चाहिए।
- इस योजना में विभिन्न चरणों में मामलों को शामिल किया गया है, जो धोखाधड़ी, दुरुपयोग, जानबूझकर मिथ्याकरण और पूरी तरह से वसूल किए गए नुकसान के लिए बहिष्करण के अधीन हैं। आवेदन ईपीएफओ नियोक्ता पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाते हैं।
- **एमनेस्टी, 2026: यह प्रतिष्ठानों को अपने भविष्य निधि पीएफ ट्रस्टों को नियमित करने में मदद करने के लिए ईपीएफओ द्वारा शुरू की गई एक बार की योजना है।** इसमें आयकर अधिनियम, 1961 के तहत मान्यता प्राप्त ट्रस्ट शामिल हैं, लेकिन ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 या सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत औपचारिक छूट का अभाव है। यह योजना 28 दिसंबर, 2026 तक खुली है।
- पात्र प्रतिष्ठान ट्रस्ट की स्थापना से लेकर निर्धारित कट-ऑफ तिथि तक पूर्वव्यापी रूप से छूट प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना निर्दिष्ट न्यूनतम कर्मचारी संख्या और निधि आवश्यकताओं को भी माफ करती है।
- पात्र ट्रस्टों ने वैधानिक योगदान जमा किया होगा और सदस्यों के खातों में लागू ईपीएफ दर के बराबर या उससे अधिक दरों पर ब्याज जमा किया होगा। इन शर्तों के अधीन, केवल इसलिए शुरू की गई कार्यवाही वापस ले ली जाएगी क्योंकि औपचारिक छूट गायब थी, और इस आधार पर कोई नई कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी।



Result Mitra

डिजिटल एक्सेस के साथ पंजीकरण का सरलीकरण

- **स्वचालित पंजीकरण:** फरवरी 2020 से, पात्र सार्वजनिक और निजी लिमिटेड कंपनियां और एक व्यक्ति कंपनियां कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय पोर्टल के माध्यम से स्वचालित ईपीएफओ पंजीकरण की सुविधा का लाभ उठा सकती हैं। यह सुविधा स्पाइस+ **और एजिल-प्रो फॉर्म** के माध्यम से संचालित होती है। यह फॉर्म विभिन्न सेवाओं जैसे पैन/टैन/निदेशक पहचान संख्या/जीएसटीएन, आदि को जोड़ती है।
- **यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) का स्व-निर्माण:** नवंबर 2019 से, कर्मचारी स्वतंत्र रूप से अपना यूएएन जनरेट करने में सक्षम हैं। यह सुविधा ईपीएफओ की सामाजिक-सुरक्षा योजनाओं में नामांकन का समर्थन करती है। अप्रैल 2025 में, ईपीएफओ ने **आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से यूएएन जनरेशन और एक्टिवेशन की शुरुआत की**। उमंग मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से उपलब्ध, यह सुविधा संपर्क रहित और सुरक्षित डिजिटल एक्सेस को सक्षम बनाती है। अक्टूबर 2026 तक, **1.74 करोड़ स्व-जनित यूएएन** की सूचना दी गई है। इसके अलावा, **जनवरी 2017 से 21 अक्टूबर तक** उमंग एप्लिकेशन पर ईपीएफओ लेनदेन **709 करोड़ से अधिक हैं, जो** ईपीएफओ सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के पैमाने को दर्शाते हैं।

- यूएएन एक अद्वितीय, स्थायी नंबर है जो ईपीएफओ सदस्य को सौंपा गया है, जो विभिन्न प्रतिष्ठानों में उनके भविष्य निधि खातों को जोड़ता है। यह भविष्य निधि संचय की पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रदान करता है जब सदस्य रोजगार बदलते हैं, जो नियोक्ता द्वारा यूएएन डेटाबेस में उनके विवरण के सत्यापन के अधीन है।

- **सरलीकृत आधार सीडिंग:** अगस्त 2025 से, ईपीएफओ सदस्य यूएएन सदस्य पोर्टल के माध्यम से आधार विवरण को सीड या सही करने में सक्षम हैं। आधार और यूएएन प्रोफाइल विवरण मेल खाने पर नियोक्ता सीधे अनुरोधों को स्वीकार कर सकते हैं। बेमेल विवरण को सुधार के लिए ईपीएफओ कार्यालय में ऑनलाइन भेजा जा सकता है। यदि नियोक्ता अनुपलब्ध है, तो सदस्य संबंधित ईपीएफओ कार्यालय के जनसंपर्क अधिकारी के माध्यम से सहायता ले सकते हैं।

ईपीएफओ सेवाओं का डिजिटल परिवर्तन

- **केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस):** सीपीपीएस पूरे भारत में किसी भी बैंक शाखा के माध्यम से पेंशन वितरण को सक्षम बनाता है। पेंशनभोगी स्थानों या बैंक शाखाओं को बदलते समय कार्यालयों के बीच पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) स्थानांतरित किए बिना अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इससे विशेष रूप से उन पेंशनभोगियों को लाभ होता है जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं। इसके अलावा, यह प्रणाली पेंशन शुरू होने के समय किसी भी सत्यापन के लिए शाखा में जाने की आवश्यकता को कम करके पेंशनभोगियों का भी समर्थन करती है।
- **डोरस्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सर्विसेज:** ईपीएफओ ने ईपीएस पेंशनभोगियों को डोरस्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सेवाएं प्रदान करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के साथ साझेदारी की है। ईपीएफओ प्रति प्रमाणपत्र 50 रूपए की लागत वहन करता है, जिससे पेंशनभोगियों के लिए सेवा मुफ्त हो जाती है। यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बुजुर्ग पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचाती है। यह समय पर पेंशन निरंतरता, पारिवारिक पेंशन की तेजी से शुरुआत और सीपीपीएस के तहत बेहतर सटीकता का समर्थन करता है।
- **पुन: डिज़ाइन की गई ईपीएफओ वेबसाइट**: 1 नवंबर, 2025 को, ईपीएफओ ने epfo.gov.in में अपनी पुन: डिज़ाइन की गई वेबसाइट लॉन्च की। मोबाइल-उत्तरदायी पोर्टल कर्मचारियों, नियोक्ताओं और पेंशनभोगियों के लिए एक एकीकृत इंटरफ़ेस प्रदान करता है। यह पासबुक, दावा फॉर्म, पेंशन सेवाओं, प्रोफ़ाइल अपडेट और योजना की जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करता है। अलग-अलग लॉगिन विकल्प और **"ईपीएफओ और आप"** अनुभाग उपयोगकर्ताओं को सेवाओं का शीघ्रता से पता लगाने में मदद करते हैं। यूट्यूब वीडियो पीएफ बैलेंस चेक करने, अग्रिम के लिए आवेदन करने, पेंशन आवेदन जमा करने, इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (ईसीआर) दाखिल करने, प्रतिष्ठानों को पंजीकृत करने और यूएएन को सक्रिय करने जैसी सेवाओं की व्याख्या करते हैं। छोटा डोमेन और बेहतर नेविगेशन सभी डिवाइसों तक पहुंच को आसान बनाता है।
- **ईपीएफओ 3.0 - कोर बैंकिंग-आधारित परिवर्तन**: ईपीएफओ 3.0 उद्योग-मानक कोर बैंकिंग क्षमताओं के माध्यम से सेवाओं का आधुनिकीकरण करता है।
- यह खाता प्रबंधन, उद्यम संसाधन योजना, अनुपालन और ग्राहक सेवाओं के लिए क्लाउड-नेटिव, एपीआई-फर्स्ट और माइक्रोसर्विसेज-आधारित मॉड्यूल के साथ एक कोर बैंकिंग समाधान को एकीकृत करता है। इसका चरणबद्ध कार्यान्वयन सुरक्षित और निर्बाध सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह पहल **कागजी कार्रवाई को कम करती है, दावों को तेज करती है और सदस्य सेवाओं के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करती है।**
- जोखिम-मान्य दावों को मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना स्वचालित प्रसंस्करण के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो संभावित रूप से **निपटान समय को 20 दिनों से घटाकर 3 दिनों से कम कर देता है।**
- नियोजित क्षमताओं में तत्काल निकासी, बहुभाषी स्वयं-सेवा और निर्बाध पेरोल-लिंक्ड योगदान शामिल हैं। इस ढांचे का उद्देश्य 30 करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए ईपीएफओ की सेवाओं का समर्थन करना है।

ईपीएफओ से परे: भारत का व्यापक सामाजिक-सुरक्षा ढांचा

- भारत का सामाजिक सुरक्षा ढांचा कई योजनाओं और संस्थागत तंत्रों के माध्यम से ईपीएफओ से आगे तक फैला हुआ है, जो रोजगार श्रेणियों में कमजोर समूहों और श्रमिकों का समर्थन करता है। ये पहल सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच को व्यापक बनाने के लिए सामाजिक सहायता, पेंशन सहायता, वैधानिक सुरक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म को जोड़ती हैं।

प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना

- यह योजना पात्र बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों और शोक संतप्त परिवारों को **सामाजिक सहायता प्रदान करती है। इसे** अक्टूबर, 2026 में मौजूदा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) से संशोधित किया गया है। **यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक जारी रहेगी।** एनएसएपी के तहत उप-योजनाओं द्वारा दिए जाने वाले लाभ निम्नलिखित हैं:

- **विकलांगता पेंशन योजना** 80 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को 375 रूपए और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को 625 रूपए की मासिक सहायता प्रदान करती है। बेंचमार्क विकलांगता सीमा को 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है और न्यूनतम आयु मानदंड को हटा दिया गया है, जिससे जन्म से पात्रता बढ़ गई है।

- **वृद्धावस्था पेंशन योजना** 60-79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को 200 रुपये और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 500 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करती है।

- **विधवा पेंशन योजना** 40-79 वर्ष की विधवाओं को 300 रूपए और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु की विधवाओं को 500 रूपए की मासिक पेंशन प्रदान करती है।

- **पारिवारिक लाभ योजना** 18-59 वर्ष की आयु के प्राथमिक कमाने वाले की मृत्यु पर पात्र परिवारों को 20,000 रूपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

- यह सामाजिक **सुरक्षा से संबंधित नौ मौजूदा केंद्रीय श्रम कानूनों को एक एकीकृत विधायी ढांचे में समेकित करता है।** संहिता भविष्य निधि, पेंशन, बीमा, मातृत्व लाभ, ग्रेच्युटी और श्रमिक सुरक्षा के अन्य रूपों को कवर करने वाले सामाजिक सुरक्षा लाभों का प्रावधान करती है। इसके प्रावधान गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित संगठित और असंगठित श्रमिकों तक फैले हुए हैं।

- संहिता लागू शर्तों के अधीन एक वर्ष की सेवा के बाद आनुपातिक आधार पर पात्र निश्चित अवधि के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी **प्रदान करती** है। यह सामाजिक सुरक्षा ढांचे के भीतर गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मान्यता देता है और सामाजिक सुरक्षा कोष द्वारा समर्थित उनके कल्याण के लिए योजनाओं का प्रावधान करता है।

- महिला-केंद्रित प्रावधानों में **पात्र महिलाओं के लिए 26 सप्ताह तक के मातृत्व लाभ,** घर से काम करने का विकल्प शामिल है, जहां निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले प्रतिष्ठानों में वर्क परमिट और क्रेच सुविधाएं शामिल हैं। संहिता कार्यान्वयन और सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच की सुविधा के लिए डिजिटल और सरलीकृत अनुपालन तंत्र भी प्रदान करती है।

Result Mitra

Result Mitra

- **ई-श्रम: असंगठित श्रमिकों के लिए एक एकीकृत मंच**
- अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया, ई-श्रम **ने असंगठित श्रमिकों का भारत का पहला आधार-सीडेड राष्ट्रीय डेटाबेस** बनाया। प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को एक यूएएन प्राप्त होता है। पोर्टल ने अगस्त 2026 तक 31.89 करोड़ पंजीकरण दर्ज किए। अक्टूबर 2024 में शुरू किया गया ई-श्रम वन-स्टॉप सॉल्यूशन, 15 सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत करता है। यह श्रमिकों को रोजगार के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा, कौशल और प्रशिक्षुता के लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब और पात्र सरकारी योजनाओं की पहचान करने के लिए माईस्कीम से भी जोड़ता है।
- **प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम)**
- पीएम-एसवाईएम 18-40 वर्ष की आयु के पात्र असंगठित श्रमिकों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिनकी मासिक आय 15,000 रूपए तक है। यह निर्धारित शर्तों के अधीन 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रतिमाह 3,000 रूपए की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान करता है। नामांकन की आयु के आधार पर मासिक योगदान 55 से 200 रूपए तक होता है, जिसमें केंद्र सरकार का समान योगदान होता है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा का समर्थन करती है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 50 प्रतिशत का योगदान देती है।

Result Mitra

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारत में सामाजिक सुरक्षा और कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) कवरेज के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ईपीएफओ (EPFO) पात्र सदस्यों को भविष्य निधि बचत, पेंशन और बीमा लाभ प्रदान करता है।
2. हालिया संशोधनों के अनुसार, अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है।
3. ई-श्रम पोर्टल जैसी पहलें केवल संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए शुरू की गई हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न

- **प्रश्न:** "भारत में व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार कार्यबल को मजबूती प्रदान करने के साथ-साथ समावेशी विकास के लिए अनिवार्य है।" पीआईबी (PIB) की इस पृष्ठभूमि के आलोक में भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों (जैसे ईपीएफओ और ई-श्रम) के समक्ष मौजूद चुनौतियों और इसके विस्तार की आवश्यकता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)

Result Mitra

पत्र सूचना कार्यालय
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

जीएसएलवी-F18/एनवीएस-03 मिशन

प्रविष्टि तिथि: 01 NOV 2026 11:15 AM

GSLV-F18
NVS-03

भारत की स्वदेशी नेविगेशन क्षमताओं को मज़बूत करना

NVS-03 मिशन: NavIC के क्षितिज का विस्तार

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 30 अक्टूबर 2026 को 23:51 बजे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी), श्रीहरिकोटा से **जीएसएलवी-एफ18/एनवीएस-03 मिशन** को सफलतापूर्वक पूरा किया।



- GSLV-F18 लॉन्च व्हीकल ने नेविगेशन सैटेलाइट NVS-03 को एक सटीक जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) में स्थापित किया। इसके बाद, 31 अक्टूबर 2026 को 16:48 बजे पहला ऑर्बिट मैन्यूवर (कक्षा संबंधी युक्ति) पूरा किया गया। इसे 111.75° पूर्व में इसके निर्धारित जियोसिंक्रोनस ऑर्बिटल स्लॉट में पहुँचाने के लिए आगे और भी मैन्यूवर किए जाने की योजना है।
- यह उपग्रह **भारत के अगली पीढ़ी के पांच नौवहन उपग्रहों की श्रृंखला का तीसरा उपग्रह** है। इसे भारतीय नक्षत्र के साथ नौवहन (NavIC) को मजबूत करने और उपग्रह आधारित नौवहन में भारत की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है।

मिशन की मुख्य बातें

- **सफल लॉन्च:** GSLV-F18 ने NVS-03 को उसके तय जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) में पहुंचाया। यह **भारत के सैटेलाइट नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर** को मज़बूत करने की कोशिशों में एक और मील का पत्थर है।
- **20वीं जीएसएलवी उड़ान:** यह मिशन भारत के जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की 20वीं उड़ान है। यह दिखाता है कि स्ट्रेटेजिक स्पेस मिशन के लिए भारत के लॉन्च व्हीकल का लगातार ऑपरेशनल इस्तेमाल हो रहा है।
- **नेक्स्ट-जेनरेशन सीरीज़ सैटेलाइट:** NVS-03, सेकंड-जेनरेशन NavIC सैटेलाइट (NVS-01 से NVS-05) का तीसरा सैटेलाइट है। इन सैटेलाइट को भारत के रीजनल नेविगेशन सिस्टम की कवरेज, सटीकता और भरोसे को मज़बूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

क्या आप जानते हैं? भू-समकालिक या भू-स्थिर कक्षा में जाने वाले अंतरिक्ष यान को आमतौर पर पहले दीर्घवृत्ताकार भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा (जीटीओ) में स्थापित किया जाता है। इस कक्षा में पृथ्वी से निकटतम बिंदु (उपभू) कम ऊंचाई पर और पृथ्वी से सबसे दूर का बिंदु (अपभू) अधिक ऊंचाई पर होता है। सामान्य जीटीओ में अपभू पृथ्वी की सतह से लगभग 35,786 किलोमीटर ऊपर होता है। अपभू के निकट अंतरिक्ष यान अपनी कक्षा में उपभू की ऊंचाई बढ़ाने और कक्षा को वृत्ताकार बनाने के लिए अपने प्रणोदन तंत्र को चालू करता है। लक्षित कक्षा के अनुसार, कक्षा के झुकाव और स्थिति में बदलाव करने के लिए अतिरिक्त प्रक्रियाएँ भी की जा सकती हैं। कक्षा की ऊंचाई बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रणोदन तंत्र को आमतौर पर अपभू मोटर कहा जाता है। **एनवीएस-03 के मामले में, कक्षा की ऊँचाई बढ़ाने की प्रक्रिया इसके तरल अपभू मोटर (एलएएम) का उपयोग करके पूरी की गई। यह रासायनिक रॉकेट इंजन का एक प्रकार है।**

Result Mitra

उपग्रह नौवहन प्रणाली

- उपग्रह नौवहन प्रणाली उपग्रहों का एक नेटवर्क है, जो स्थिति निर्धारण, नौवहन और समय संबंधी जानकारी उपलब्ध कराता है। ये उपग्रह लगातार ऐसे संकेत प्रसारित करते हैं, जिनमें उनकी स्थिति और सटीक समय की जानकारी होती है। स्मार्टफोन, वाहनों और नौवहन उपकरणों जैसे अभिग्राहक अनेक उपग्रहों से प्राप्त संकेतों का उपयोग करके अपनी सटीक स्थिति, गति और दिशा निर्धारित करते हैं। ये प्रणालियाँ मार्ग नौवहन, विमान और जहाजों की निगरानी, सटीक कृषि, आपदा प्रबंधन और दूरसंचार सहित कई कार्यों में सहायता करती हैं। इनके उदाहरणों में अमेरिका की **ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस)** और भारत की **भारतीय नक्षत्र के साथ नौवहन (नाविक)** प्रणाली शामिल हैं।

- **बेहतर नौवहन संकेत:** एनवीएस-03 में एल1, एल5 और एस आवृत्ति बैंड में नौवहन पेलोड लगाए गए हैं। एल5 और एस संकेतों के साथ एल1 संकेत को शामिल करने से नाविक की क्षमताओं और अनुकूलता में और वृद्धि होगी। यह भारत के भूभाग और इसकी भू-राजनीतिक सीमा से 1,500 किलोमीटर आगे तक के क्षेत्र में नौवहन कवरेज प्रदान करने में सहायता करता है।

- कई आवृत्ति बैंड के उपयोग से अनुकूल अभिग्राहक अलग-अलग आवृत्तियों पर प्रसारित संकेतों को प्राप्त कर सकते हैं। इससे विभिन्न अनुप्रयोगों और परिचालन परिस्थितियों के अनुकूल अभिग्राहक तैयार करने के विकल्प भी उपलब्ध होते हैं।

नौवहन संकेत और उनके आवृत्ति बैंड

- **नौवहन संकेत** रेडियो आवृत्ति वाले संकेत होते हैं, जिन्हें नौवहन उपग्रह पृथ्वी पर स्थित अभिग्राहकों तक प्रसारित करते हैं। इन संकेतों में सटीक समय और उपग्रह की स्थिति से संबंधित जानकारी होती है। अभिग्राहक इस जानकारी का उपयोग करके अपनी स्थिति, गति और समय की गणना करते हैं। **आवृत्ति बैंड** रेडियो आवृत्तियों की निश्चित सीमाएं होती हैं, जिनका उपयोग इन संकेतों को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। उपग्रह नौवहन प्रणालियाँ रेडियो आवृत्ति स्पेक्ट्रम के निर्धारित हिस्सों का उपयोग करती हैं। अलग-अलग बैंड के माध्यम से संकेतों को विभिन्न आवृत्तियों पर प्रसारित और प्राप्त किया जा सकता है।

- **स्वदेशी तकनीक:** एनवीएस-03 में खरीदी गई परमाणु घड़ियों के साथ-साथ स्वदेश में विकसित परमाणु घड़ी भी लगाई गई है। ये घड़ियाँ नौवहन संकेत तैयार करने के लिए अत्यंत सटीक समय का संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। संकेतों को तय की गई दूरी तय करने में लगने वाले समय का पता लगाने और उपयोगकर्ताओं की स्थिति की गणना करने के लिए सटीक समय का होना आवश्यक है।

- **व्यापक उपयोग:** एनवीएस-03 भारत की स्वतंत्र स्थिति निर्धारण, नौवहन और समय (पीएनटी) संबंधी क्षमताओं को मजबूत करता है। इन क्षमताओं से परिवहन, समुद्री संचालन, विमानन, आपदा प्रबंधन, सटीक कृषि और रणनीतिक सेवाओं सहित कई क्षेत्रों में सहायता मिलती है।

Result Mitra

भू-समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान (जीएसएलवी)

- भू-समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान (जीएसएलवी) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा विकसित तीन चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। इसका उपयोग उपग्रहों को भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा (जीटीओ) और निम्न पृथ्वी कक्षा (एलईओ) में स्थापित करने के लिए किया जाता है। जीएसएलवी की विशेषता, जो इसे अन्य प्रक्षेपण यानों से अलग बनाती है, इसका अंतिम चरण है। इसमें स्वदेश में विकसित क्रायोजेनिक ऊपरी चरण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, जीएसएलवी में इस्तेमाल होने वाले बूस्टर तरल ईंधन से संचालित होते हैं, जिन्हें आमतौर पर एल-40 के नाम से जाना जाता है। इनमें नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड (N_2O_4) और यूएच-25 के हाइपरगोलिक मिश्रण का उपयोग किया जाता है। यूएच-25 में 75 प्रतिशत असममित डाइमेथिलहाइड्राजीन (यूडीएमएच) और 25 प्रतिशत हाइड्राजीन हाइड्रेट होता है।
- जीएसएलवी-एफ18 की ऊँचाई लगभग 50 मीटर है और प्रक्षेपण के समय इसका भार लगभग 420 टन होता है। इसमें 3.4 मीटर व्यास वाला धातु का पेलोड फेयरिंग लगा है। इसने लगभग 2,250 किलोग्राम वजनी नौवहन उपग्रह एनवीएस-03 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया।
- **क्रायोजेनिक ऊपरी चरण:** क्रायोजेनिक ऊपरी चरण प्रक्षेपण यान का अंतिम चरण होता है। इसमें ऐसे प्रणोदकों का उपयोग किया जाता है, जो उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षाओं में स्थापित करने के लिए आवश्यक उच्च दक्षता प्रदान करते हैं। जीएसएलवी में इस्तेमाल होने वाले इसरो के स्वदेशी क्रायोजेनिक ऊपरी चरण में ईंधन के रूप में तरल हाइड्रोजन (LH_2) और ऑक्सीकारक के रूप में तरल ऑक्सीजन (LOX) का उपयोग किया जाता है। इन दोनों को अत्यंत कम तापमान पर रखा जाता है। इसने जीएसएलवी की शुरुआती उड़ानों में इस्तेमाल किए जाने वाले रूस से प्राप्त चरण का स्थान लिया। इससे उन्नत प्रक्षेपण यान तकनीक के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता मजबूत हुई है।

Result Mitra

NavIC को समझें: भारत की स्वदेशी नौवहन प्रणाली

- · NavIC भारत की क्षेत्रीय उपग्रह नौवहन प्रणाली है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने विकसित किया है।
- · इसे पहले भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली (आईआरएनएसएस) के नाम से जाना जाता था।
- · यह प्रणाली उपयोगकर्ताओं को स्थिति निर्धारण, नौवहन और समय (पीएनटी) संबंधी सेवाएं प्रदान करती है।
- NavIC को मूल रूप से सात उपग्रहों के समूह के साथ तैयार किया गया था। इसे चौबीसों घंटे काम करने वाले भू-स्टेशनों के नेटवर्क का सहयोग प्राप्त है। इसकी संरचना में तीन उपग्रह भू-स्थिर कक्षा में और चार उपग्रह झुकी हुई भू-समकालिक कक्षा में स्थापित हैं। मौजूदा उपग्रह समूह की क्षमता बढ़ाने और नौवहन सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एनवीएस श्रृंखला के उपग्रह स्थापित किए जा रहे हैं।
- NavIC भारत के भूभाग और इसकी भू-राजनीतिक सीमा से लगभग 1,500 किलोमीटर आगे तक के क्षेत्र में सेवाएँ प्रदान करता है।
- एनवीएस श्रृंखला में पहले से इस्तेमाल हो रहे एल5 और एस संकेतों के साथ एल1 संकेत भी जोड़ा गया है।

दो प्रकार की नौवहन सेवाएं

- NavIC आम नागरिकों और अधिकृत रणनीतिक उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो प्रकार की नौवहन सेवाएं प्रदान करता है।
- **मानक स्थिति निर्धारण सेवा (एसपीएस):** यह एक खुली नौवहन सेवा है, जो आम नागरिकों के उपयोग के लिए उपलब्ध है। NavIC के एसपीएस संकेत अन्य वैश्विक उपग्रह नौवहन प्रणालियों (जीएनएसएस) के संकेतों के साथ भी काम कर सकते हैं। इनमें अमेरिका का जीपीएस, रूस का ग्लोनास, यूरोपीय संघ का गैलीलियो और चीन का बेइदौ शामिल हैं।
- **प्रतिबंधित सेवा (आरएस):** यह एक कूटबद्ध नौवहन सेवा है, जो केवल रणनीतिक उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है।

अगली पीढ़ी की नौवहन उपग्रह श्रृंखला की प्रगति

- नाविक उपग्रह समूह की क्षमता बढ़ाने और स्वदेशी नौवहन सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए पांच उपग्रहों वाली एनवीएस श्रृंखला विकसित की जा रही है। अब तक एनवीएस-01, एनवीएस-02 और एनवीएस-03 का प्रक्षेपण किया जा चुका है, जबकि एनवीएस-04 और एनवीएस-05 का प्रक्षेपण किया जाना बाकी है। इसरो नाविक सेवाओं के कवरेज, विश्वसनीयता और उपलब्धता को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है।

Result Mitra

एनवीएस-01 – अगली/दूसरी पीढ़ी की श्रृंखला का पहला उपग्रह

- भारत के जीएसएलवी की 15वीं उड़ान जीएसएलवी-एफ12 ने एनवीएस-01 को भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित किया।
- एनवीएस-01 का प्रक्षेपण 29 मई 2023 को किया गया था। यह दूसरी पीढ़ी की नाविक उपग्रह श्रृंखला का पहला उपग्रह है। इसे नाविक की पहले से उपलब्ध सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है।
- इसमें एल1, एल5 और एस बैंड में नौवहन पेलोड लगाए गए हैं।
- प्रक्षेपण के समय इसका भार लगभग 2,232 किलोग्राम था।
- एनवीएस-01 का निर्धारित मिशन जीवनकाल 12 वर्ष है।
- इसमें अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र द्वारा विकसित स्वदेशी रूबिडियम परमाणु घड़ी लगाई गई है।

एनवीएस-02 – इस श्रृंखला का दूसरा उपग्रह

- एनवीएस-02 का प्रक्षेपण 29 जनवरी 2025 को जीएसएलवी-एफ15 के माध्यम से किया गया था।
- इसमें एल1, एल5 और एस बैंड के नौवहन पेलोड के साथ-साथ सी-बैंड का रेंजिंग पेलोड भी लगाया गया है।
- प्रक्षेपण के समय एनवीएस-02 का भार 2,250 किलोग्राम था।
- इसमें सटीक समय का आकलन करने के लिए स्वदेशी और खरीदी गई परमाणु घड़ियों का उपयोग किया गया है।
- प्रक्षेपण के बाद ऑक्सीकारक के वाल्व नहीं खुलने के कारण उपग्रह की कक्षा को ऊंचा करने की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी। परिणामस्वरूप, उपग्रह अपनी निर्धारित कक्षीय स्थिति तक नहीं पहुंच सका।

एनवीएस-04 और एनवीएस-05 – आगामी उपग्रह

- एनवीएस-04 और एनवीएस-05 दूसरी पीढ़ी की नाविक उपग्रह श्रृंखला के लिए नियोजित चौथे और पाँचवें उपग्रह हैं।
- पहले के एनवीएस उपग्रहों की तरह, इन दोनों में भी एल5 और एस बैंड के साथ एल1 संकेत प्रसारित करने की अपेक्षा है। इन दोनों उपग्रहों को बेहतर नौवहन क्षमताएँ प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है।

भारत की अंतरिक्ष संप्रभुता की दिशा में एक और कदम

- अगली पीढ़ी के नाविक उपग्रहों का सफल विकास और प्रक्षेपण उन्नत अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वदेशी उपग्रह नौवहन क्षमताओं को मजबूत करके भारत स्वतंत्र रूप से विश्वसनीय स्थिति निर्धारण, नौवहन और समय संबंधी सेवाएँ प्रदान करने की अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। इन प्रगतियों से महत्वपूर्ण कार्यों के लिए विदेशी उपग्रह नौवहन प्रणालियों पर निर्भरता कम होगी। साथ ही, इससे रणनीतिक अंतरिक्ष बुनियादी ढाँचे के निर्माण, विकास और संचालन के लिए भारत की तकनीकी क्षमता भी मजबूत होगी। ये प्रयास भारत की अंतरिक्ष संप्रभुता, तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ती भूमिका को और सुदृढ़ करते हैं।

Result Mitra

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: हाल ही में चर्चा में रहे जीएसएलवी-एफ18/एनवीएस-03 मिशन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस मिशन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी), श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक पूरा किया गया है।
2. यह मिशन भारत की स्वदेशी नेविगेशन क्षमताओं (NavIC) को मजबूत करने से संबंधित है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1, न ही 2

मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न

- **प्रश्न:** "अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन प्रणालियाँ सामरिक स्वायत्तता, आपदा प्रबंधन और सटीक भू-स्थानिक सेवाओं (Geospatial Services) के लिए रीढ़ की हड्डी होती हैं।" भारत के **NavIC (NVS-03)** जैसे स्वदेशी नेविगेशन मिशनों के महत्व और देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता में इनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)

महत्वपूर्ण तथ्य

Why even a strong El Niño does not guarantee a poor Indian monsoon

Seven Indian monsoons since 1990 have run into a moderate or strong El Niño; of these, in five years, including 2026, monsoon rainfall levels were at least 10% lower than the long-term average; the IMD refers to this level as 'deficient'. the 2023 season was something of an exception with 'below average' rainfall; however, 1997 had 'average' rainfall

Ankit Mishra

In the summer of 1997, one of the strongest El Niños of the 20th century took shape in the Pacific Ocean. The India Meteorological Department (IMD) predicted a monsoon rainfall deficit of 8% below the average, as was expected in El Niño years. However, by the end of September that year, rainfall levels were nearly normal.

This year, a "firm-to-be" El Niño is taking shape, and is expected to peak only in December. The 2026 southwest monsoon ended nearly 10% below the long-term average of 87 cm. East and Northeast India had their driest season since records began in 1901.

So what happened differently in 1997?

El Niño and the monsoon

Near the Earth's equator, steady winds blow across the Pacific Ocean from east to west. These winds drive warm surface water into Indonesia. The water then warms the air over it, and the warm air rises, creating rain clouds.

These winds diminish every 2-7 years. The warm water flows back east to South America, with the rain clouds trailing behind. Scientists call this phenomenon the El Niño Southern Oscillation.

This upsurge of warmer air from the Pacific eventually has to descend somewhere — and our portion sinks over India. As the air subsides, it becomes warmer and drier, and rain clouds struggle to form in it, which can weaken monsoon rains.

Records maintained by the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration show that seven Indian monsoons since 1990 have run into a moderate or strong El Niño. Of these, in five years, including 2026, monsoon rainfall levels were at least 10% lower than the long-term average. The IMD refers to this level as "deficient". The 2023 season was something of an exception with 'below average' rainfall.

Nonetheless, only 1997 had average rainfall.

During the monsoons, the 1997 and the 2026 El Niño were about equally strong. Sea surface temperatures in the equatorial Pacific were 1.64 degree Celsius above normal in 1997 and 1.59 degree Celsius in 2026, according to NOAA's Oceanic Niño Index. This year the figure was 1.98 degree Celsius.

Nevertheless, India received normal rainfall in 1997 but around 13% less than the normal in 2026. This is partly because of another ocean.

Indian Ocean Dipole

Like the Southern Oscillation, there is a see-saw in the Indian Ocean as well called the Indian Ocean Dipole (IOD). One end of the IOD is in the west, near Africa, and the other is in the east, near Indonesia. In specific years, the western extremity becomes warmer than usual and the eastern extremity cooler. This is known as the positive phase and is beneficial to India. The air over the warmer western waters rises more strongly, draws moist winds, and the monsoon carries more of that moisture over India. In most years, there is no tendency towards either end and the IOD is said to be neutral.



Scorched Earth: A farmer staying at a patch of dry agricultural land in Dharmagarh, Kalahandi, Ca. district

The IOD tends to dip around June and is most pronounced September to November, which means its impact tends to be later in the monsoon. And it tends to go into the positive phase when an El Niño occurs.

The see-saw shifted in India's favour in 1997 and offset the El Niño. In 2015, however, it barely missed. One 2024 study by researchers from India and the U.S., including IIT-Delhi, IIT-Kharagpur, NIT-Rourkela found why: a change in the belt of winds that encircles Antarctica sent westerly winds across the southern Indian Ocean, which kept the see-saw from tipping.

The IOD was again favourable in 2023. According to IMD, India received 26% less rain than normal in August 2023, the driest August since 1901.

The Department partly blamed the Madden-Julian Oscillation, a wave of clouds and rain that passes around the tropics every 30 to 60 days, which resided over Africa and the Americas during the month. The see-saw tipped in India's favour in late August and early September and extended itself into the seas off Indonesia, where it favours rains over the subcontinent.

Where an El Niño's warmest water sits also affects India's rain, according to a 2006 study in *Science*. If that water is in the middle of the Pacific Ocean, the sinking air is more likely to settle on India, which increases the odds of less rain. In 1997, the warmest waters were located further east around South America.

A study published this July in *Nature Communications* suggested that the see-saw is not the only explanation for 1997.

It also indicated other factors that occurred in July and August, notably an unusual high-pressure system high above the Iranian plateau in West Asia and additional moisture coming in from the Arabian Sea. The study also said that 1983 and 1997 were two years that made El Niño's influence on the monsoon appear less powerful than it was in reality.

Farmers and food prices

Seasons like 1997 are easier to explain in hindsight than in advance. Since 1997, IMD has changed its approach, and now updates its April forecast at the end of May. Also, since 2021, it has combined the forecasts of several global climate models into one. In both 2023 and 2026, both El Niño years, the season's rainfall levels fell within the error margin of IMD's forecast. In 2023 it forecast 96% of the long-term average, give or take 5 points, and the season ended at 94.7%. For 2026 it forecast 92%, give or take 5 points, and the season ended at 87.4%.

That said, this year was not spared complications or surprises. The IMD predicted the monsoon to be "below normal" in April but it turned out to be "deficient". Only one of its four regional forecasts, for the south peninsula, came true.

Forecasters also disagreed about the IOD's see-saw. In April, IMD said "the latest climate models" showed the IOD turning positive towards the end of the monsoon season, and in early September the WMO still expected a positive IOD between September and November. The IMD's own model predicted the IOD would remain neutral from late May. Its records show it was neutral throughout the season.

The monsoon brings about three-quarters of India's yearly rain. About 40% of the country's farmland has no irrigation and depends on it, per the agriculture ministry's latest figures. Farmers plan their sowing around the forecast and officials use it to manage food stocks and water releases from dams. The onset of a weak monsoon thus reduces farmers' incomes and leads to higher food prices. IMD's May forecast also warned of "pressure on drinking water resources" nationwide.

Ankit Mishra is an ICSSR Doctoral Fellow at the U.S. Port Social Science Institute, where his research focuses on environment, climate change, water, and forests. ankitmishra@uwm.edu

THE GIST

The Indian Ocean Dipole turned [illegible] in 2023 and had little effect in 2026, with only 2024 study linking this to varied changes around Antarctica that prevented the dipole from strengthening.

IMD has improved its monsoon forecasting since 1997 by updating its April forecast in late May and, since 2021, using a combination of multiple global climate models.

Despite El Niño conditions in 2023 and 2026, seasonal rainfall remained within the forecast error margin, highlighting gains in forecast accuracy.

YouTube Homework

- El-Nino
- La-Nina

महत्वपूर्ण तथ्य

1. मुख्य विषय (Key Theme)

- अल नीनो (El Niño) के होने से हमेशा भारत में सूखा या खराब मानसून ही आएगा, ऐसा अनिवार्य नहीं है (जैसे: 1997 में अल नीनो के बावजूद सामान्य बारिश हुई थी)।
- 1950 के बाद से अल नीनो वाले 7 वर्षों में से 5 वर्षों (2026 सहित) में बारिश में कमी दर्ज की गई, जबकि 1997 सामान्य रहा।

2. अल नीनो का प्रभाव कम होने के मुख्य कारण

- **इंडियन ओशन डिपोल (IOD):**
  - हिंद महासागर का 'सकारात्मक (Positive) IOD' अल नीनो के प्रतिकूल प्रभाव को बेअसर (offset) कर देता है और भारत में नम हवाएं खींचता है। 1997 में ऐसा ही हुआ था।
- **मैडन-जूलियन ऑसिलेशन (MJO):**
  - यह बादलों और बारिश की एक लहर है, जो समय-समय पर मानसून को सहारा देती है।
- **अन्य भौगोलिक कारक:**
  - प्रशांत महासागर में गर्म पानी की सटीक स्थिति और अंटार्कटिक हवाओं के पैटर्न भी IOD और मानसून की वर्षा को प्रभावित करते हैं।

3. IMD के पूर्वानुमान और कृषि पर असर

- **पूर्वानुमान में सुधार:** 1997 के बाद से IMD ने अपने मॉडल सुधारे हैं और 2021 से कई वैश्विक जलवायु मॉडलों को मिलाकर अधिक सटीक अनुमान (Error Margin के भीतर) दे रहा है।
- **आर्थिक व कृषि महत्व:** भारत की 40% कृषि भूमि केवल मानसून पर निर्भर है। कमजोर मानसून से बुआई प्रभावित होती है, खाद्य कीमतें बढ़ती हैं और पेयजल का संकट पैदा होता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

What does the Binance hack mean for investors?

Who was responsible for the Binance hack, and what do investigators know about the attackers?

Sahana Venugopal

The story so far:

One of the world's top cryptocurrency exchange platforms, Binance, was hit by a cyberattack on October 29 that led to the loss of assets valued at over $6 billion.

How did the Binance hack take place?

On October 30, after independent crypto trackers posted warnings, Binance announced that it was aware of reports of a "potential security issue," but assured users that their funds were safe.

Binance then moved to pause deposits and withdrawals, promising they would resume after the security checks were complete – ideally within 48 hours. Deposits were later enabled again.

Hours later, Binance shared that the "security incident" led to estimated losses totalling around $6.3 billion. Adding that it worked with industry partners and other blockchain companies in order to freeze the stolen assets, Binance announced that around $3 billion had been frozen on-chain. Stablecoin companies Circle and Tether, which issue a more stable cryptocurrency pegged to the value of the U.S. dollar, said they froze assets linked to the hack.

Tether's CEO reported that Tether froze more than 1,567 billion USDT, while Circle's CEO announced that the company had frozen more than 800 million USDC. However, these statements have alienated some customers who believe in a 100% decentralised crypto system, where corporate leaders do not get involved in recovering other companies' lost funds. Some crypto advocates, though, classified this as proof of the industry coming together to mitigate cybercrimes.

According to Binance's initial investigation, the hack "may involve a compromised DevOps engineer's laptop," through which the attacker was able to access a service container and submit unauthorised withdrawal transactions.

Binance co-CEO Richard Teng defended the company's security protocols on social media. Mr. Teng stressed that the hack was a complex one, and that the attacker did not use a sole engineer's permissions or exploit a "one-click" action. Binance later disclosed "additional points of breach."

Binance said it found no evidence of any wallet private keys being leaked, and committed to sharing a detailed technical post-mortem once the facts were verified.

Binance committed to covering the stolen funds through its Secure Asset Fund for Users (SAFU) and the corporate treasury. While $5 billion of the funds were already held in the exact token assets that were impacted, per the company, it is buying the remaining amount in token assets through market channels and OTC channels.

Who is behind the Binance hack?

The Binance hackers and their motives have not yet been confirmed. However, multiple crypto hackers have the backing of hostile states, with North Korean hackers often targeting crypto exchanges as a way to get around economic sanctions. The 2024 multi-million-dollar WazirX exchange hack, for example, was attributed to the North Korean Lazarus Group. Binance did not initially name a perpetrator or accuse any individuals. However, blockchain analytics platform Chainalysis said it observed funds, which were stolen by North Korea in another exploit, commingling with funds stolen from Binance. "We have a high degree of confidence that DPRK is responsible for the $6.4 billion hack of Binance," posted Chainalysis on X, attributing the attack to the TraderTraitor cybercrime group which has links to the Lazarus Group.

However, according to Chainalysis, the pattern of laundering the stolen assets suggested that the attackers were using automation to cover their tracks and loop funds through repeated addresses.

What does this mean for the sector?

Crypto hacks generally trigger widespread panic and anger; many traders know they are investing in a largely unregulated market and have few legal protections during a crisis. This time, social media users reacted with anger over learning that a compromised employee laptop was part of the security lapse. The Binance hack rattled the crypto markets, with the Bitcoin, Ethereum's Ether, and Binance linked BNB cryptocurrencies seeing noticeable but not drastic price drops.

While Binance promised to weather the storm, it has already faced legal heat across jurisdictions. Take the U.S. Treasury, which in 2023 announced historic settlements with the exchange over its failure to stop and report suspicious transactions with terrorists, ransomware attackers, money launderers, criminals, and users in Iran, North Korea, Syria, and the Crimea region of Ukraine.

Now, the fact that the world's largest crypto exchange was exploited for billions of dollars will undoubtedly complicate Binance's already contentious operations.

महत्वपूर्ण तथ्य

- **बायनेन्स हैक (Binance Hack): निवेशकों के लिए इसका क्या अर्थ है?**

1. घटना क्या है? (What Happened?)

- दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बायनेन्स (Binance) पर एक बड़ा साइबर हमला हुआ, जिसमें **$6 अरब (लगभग $6.3 बिलियन)** से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ।
- कंपनी ने सुरक्षा जांच पूरी होने तक डिपॉजिट और विड्रॉल (निकासी) रोक दिए थे, जिन्हें बाद में बहाल कर दिया गया।

2. हैक कैसे हुआ और फंड कैसे रिकवर हुए?

- **हैक का कारण:** शुरुआती जांच के अनुसार, एक DevOps इंजीनियर के समझौता किए गए (compromised) लैपटॉप के माध्यम से अनधिकृत निकासी की गई।
- **फंड फ्रीज:** बायनेन्स ने उद्योग भागीदारों (जैसे Tether और Circle) के साथ मिलकर लगभग **$3 अरब** की संपत्ति को ऑन-चेन (on-chain) फ्रीज करवा दिया।
- **उपयोगकर्ताओं की भरपाई:** बायनेन्स ने अपने **SAFU (Secure Asset Fund for Users)** और कॉरपोरेट खजाने के जरिए उपयोगकर्ताओं के नुकसान की पूरी भरपाई (cover) करने की प्रतिबद्धता जताई है।

3. हैक के पीछे कौन है? (Who is Responsible?)

- ब्लॉकचेन एनालिसिस प्लेटफॉर्म **Chainalysis** के अनुसार, इस हैक के पीछे उत्तर कोरिया (North Korea) से जुड़े साइबरक्राइम ग्रुप **TraderTraitor (Lazarus Group)** का हाथ होने की अत्यधिक संभावना (High Confidence) है।

4. निवेशकों और क्रिप्टो क्षेत्र पर प्रभाव (Impact on Sector & Investors)

- **बाजार पर असर:** हैक के बाद Bitcoin, Ethereum और BNB जैसी प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई।
- **नियामक दबाव (Regulatory Challenges):** बायनेन्स पहले से ही अमेरिकी खजाना (US Treasury) और अन्य नियामकों के कानूनी मामलों का सामना कर रहा है; इस बड़े हैक से उसकी कानूनी और परिचालन संबंधी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

Even as unemployment falls, lack of 'decent work' in India

Anukriti Negi
Research Scholar, Department of Economics, Banaras Hindu University, Varanasi

Priyabrata Sahoo
Assistant Professor in the Department of Economics, Banaras Hindu University, and visiting Research Fellow to University of Leeds, United Kingdom

Santosh Kumar Dash
Assistant Professor at IIMA, "Tribhuvan" Sahkari University, Anand

India's unemployment rate fell from 6.1% in 2017-18 to 3.2% in 2023-24. At the same time, female workforce participation increased for the first time in decades as has been widely reported in government documents. In light of these positive developments, it is the right time to ask what kind of jobs have been generated in India recently, and what working conditions accompany them.

This is important because employment alone does not inherently ensure dignity, security, or a stable livelihood. A worker engaged in garment sewing without a formal contract, a gig worker without insurance coverage, or a construction labourer without paid leave may technically be considered employed, but they remain outside the promise of decent work. The International Labour Organization (ILO) defines 'decent work' as employment that offers equitable income, workplace rights, social security and dignity. This principle is integrated into Sustainable Development Goal 8 (SDG-8), which advocates "decent work for all". Measured this way, India's labour market persistently exhibits high levels of informality, insecure employment, and increasing inequalities.

Measuring decent work

Using two rounds of the Periodic Labour Force Survey (PLFS), 2017-18 and 2023-24, the quality of employment in India has been analysed. By constructing a multidimensional Decent Work Index (DWI) based on three subdimensions – employment status, employment opportunity, and social security – across five major industries (agriculture, manufacturing, construction, wholesale and retail, and transport), it was observed that India has made progress in improving work conditions over time. The overall DWI increased from 0.247 in 2017-18 to 0.302 in 2023-24. While this indicates some improvement in job quality, the overall level remains alarmingly low. More importantly, progress has been uneven across sectors, regions, gender and caste groups.

Manufacturing in the secondary sector and transport in the tertiary sector showed the highest improvement in decent work conditions during this period. The manufacturing sector's DWI increased from 0.324 to 0.411 due to a gradual rise in formalisation and digitalisation. The transport sector also experienced significant progress (from 0.285 to 0.35), largely due to the expansion of urban logistics and app-based platform work. However, these improvements also reveal an important concern. Even in sectors where employment conditions have improved, access to social security remains limited. A large number of workers still do not have written contracts, paid leave, provident fund benefits or insurance coverage. Though employment opportunities are increasing, labour protections and job security are not improving at the same pace. Agriculture, which continues to employ the largest share of India's workforce, remains the lowest-quality employment generating sector. The agricultural sector's DWI marginally increased from 0.281 to 0.287 during the study period; most agricultural workers continue to be self-employed or unpaid family workers without stable income or labour protections. The issue is not merely low productivity; rather it is the rise of informal jobs. Construction and retail sectors tell a similar story. Workers remain dependent on casual employment, subcontracting chains and insecure labour arrangements. Welfare schemes exist on paper but implementation gaps continue to exclude millions of workers.

Nearly 90% of India's workforce remains informally employed, a share that has risen since 2019, according to the India Employment Report 2024 (ILO-IHD). It has expanded into supply chains, app-based work in the gig and platform economy, logistics, home-based production, and in even organised industries through contractualisation and outsourcing.

The challenge becomes even more serious when viewed in the context of social inequality. The analysis by the authors shows that decent work outcomes improve significantly with education, formal enterprise employment and skill training. However, informalisation of jobs reduces decent work creation in India over time. Especially concerning is the growing intersection of caste and gender disadvantage: women from Scheduled Tribes and Other Backward Classes experienced a decline in decent work outcomes between 2017-18 and 2023-24, even as outcomes for men improved. The labour market penalty for being both female and socially marginalised has intensified after the COVID-19 pandemic. This shows that inequality in India's labour market is not just economic, it is also structurally rooted in caste and gender hierarchies.

Regional disparities further expose the uneven nature of labour market progress. States such as Goa, Kerala, Tamil Nadu, and Haryana perform substantially better in terms of decent-work creation; in contrast, Bihar, Jharkhand, and Uttar Pradesh continue to lag behind.

The findings point to a serious policy concern: while India has been able to create more jobs, it is still struggling to ensure that these jobs provide decent working conditions and security.

> Poor-quality employment generation has consequences for economic growth. Workers without social security spend less, save less and remain vulnerable to economic shocks

Poor quality employment generation has consequences for economic growth. Workers without social security spend less, save less and remain vulnerable to economic shocks. Moreover, informality depresses productivity, weakens tax capacity, and increases inequality. India cannot measure labour market success only through reduction in unemployment rates and income growth. A country aspiring to become Viksit Bharat by 2047 cannot rely indefinitely on insecure, low-paid and unprotected labour. Economic growth without decent work can create a workforce that may have jobs, but still lives with insecurity, instability and a lack of protection. India has to shift from a 'job-counting approach' to a 'job-quality approach'.

The way forward

The findings point toward where policy should focus. First, social protection must extend to all workers – gig and platform workers, self-employed, farmers, and informal workers – through systems that are portable and accessible regardless of employment status. Platforms such as e-Shram are a good start, but registering alone does not guarantee protection; workers need real protection, not just a database entry.

Second, formalisation policies should focus on labour conditions, not just business registration. Enterprises receiving tax incentives or subsidies should be linked to mandatory worker protections such as written contracts, paid leave, and social security contributions.

Third, labour policies need to be more intersectional. Given that women from marginalised caste groups are the group whose outcomes worsened rather than improved, targeted measures – childcare facilities, safe transportation, skill training and safeguards against workplace discrimination – should not be an afterthought. Finally, labour reforms should be designed around the needs of workers first, rather than being framed primarily as a means of easing the cost of doing business.

The four Labour Codes were introduced in 2025 with the promise of simplifying labour regulation and expanding protections. However, implementation remains partial and inconsistent. Critics argue that while compliance has been eased for businesses, worker protections may have diminished with rising contractualisation.

The real test of development is not whether workers have some kind of work; it is whether that work provides dignity and security. Until then, India's employment success story will remain incomplete – no nation can call itself developed while its workforce remains insecure.

YouTube Homework

- PLFS 2025
- Unemployment

महत्वपूर्ण तथ्य

- **बेरोजगारी घटने के बावजूद, भारत में 'सम्मानजनक कार्य' (Decent Work) की कमी**

1. मुख्य समस्या (The Core Issue)

- भारत में बेरोजगारी दर (2017-18 के 6.1% से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है) और कार्यबल भागीदारी में सुधार हुआ है।
- हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी को अच्छी और सुरक्षित नौकरियां मिल रही हैं। अधिकांश श्रमिकों के पास लिखित अनुबंध (written contract), सवेतन अवकाश (paid leave) या सामाजिक सुरक्षा का अभाव है।

2. मुख्य निष्कर्ष (Key Findings)

- **अनौपचारिक क्षेत्र (Informality):** भारत का लगभग 90% कार्यबल अनौपचारिक रूप से नियोजित है, और गिग इकोनॉमी (gig economy) व आउटसोर्सिंग के कारण इसमें और वृद्धि हुई है।
- **क्षेत्रीय और सामाजिक असमानता:**
  - विनिर्माण और परिवहन क्षेत्रों में कार्य स्थितियों में सुधार हुआ है, जबकि कृषि क्षेत्र में स्थिति सबसे खराब बनी हुई है।
  - गोवा, केरल, तमिलनाडु और हरियाणा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश पीछे हैं।
  - महिलाओं और हाशिए के समूहों (SC/ST/OBC) के लिए 'डिसेंट वर्क' के परिणाम पुरुषों की तुलना में और अधिक पिछड़े हैं।

3. आगे की राह (The Way Forward)

- **सामाजिक सुरक्षा का विस्तार:** ई-श्रम जैसे पोर्टल अच्छे हैं, लेकिन केवल पंजीकरण काफी नहीं है; श्रमिकों को वास्तविक सुरक्षा (जैसे सामाजिक सुरक्षा, बीमा) मिलनी चाहिए।
- **व्यापार औपचारिकरण (Formalisation):** केवल व्यवसायों के पंजीकरण के बजाय काम करने की स्थिति (जैसे लिखित अनुबंध और सवेतन अवकाश) पर ध्यान देना चाहिए।
- **नीतिगत सुधार:** श्रम सुधारों को केवल व्यवसाय सुगमता (ease of doing business) तक सीमित न रखकर श्रमिकों की सुरक्षा और गरिमा को प्राथमिकता देनी चाहिए।

महत्वपूर्ण तथ्य

CEC stole citizens' voice, will do time: Rahul

- Large crowd marches with leaders of the INDIA bloc during demonstration against 'vote theft'
- Rahul Gandhi calls for ouster of poll body chief; outlines a post-Modi vision rooted in harmony
- Ramlila Maidan has turned into 'democracy's Haldighati', says Samajwadi Party chief

Subhana K. Nair
NEW DELHI

Accusing Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar of committing "treason" by stealing the voice of citizens", the Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, on Sunday said the poll official would be removed from office. He would "go to jail", Mr. Gandhi said.

Mr. Gandhi was speaking at a rally by the Indian National Developmental, Inclusive Alliance (INDIA) at Ramlila Maidan here, which saw participation from across the country with crowds marching with drums and waving flags spilling beyond the ground's boundaries.

"The scale of today's uprising has never before been seen in Delhi," Congress general secretary K.C. Venugopal said in a post on X.

Mr. Gandhi's 18-minute-long speech continued aggressive posturing towards the Union government with a preview of what he described as a post-Narendra Modi vision of India that would replace the politics of hatred with the politics of harmony.

Responding to Union Home Minister Amit Shah's remarks that Prime Minister Modi is "not going anywhere", Mr. Gandhi said that neither the Prime Minister nor the Union Home Minister would be allowed to "go anywhere" even if they wanted to.

'2024 mandate illegal'

He said "vote theft" had been happening in the country for years, claiming several Assembly elections, including those in Madhya Pradesh, Haryana, Chhattisgarh, and Maharashtra, were stolen through the "addition" and "deletion" of voters.

The Congress leader alleged that the 2024 mandate for the Modi government was "illegal". After the 2024 Lok Sabha election, Mr. Gandhi said 150 million voters were removed – about 15% of the total electorate, or one in every seven voters. He pointed out that the difference in vote share between the BJP-led coalition and the INDIA bloc was three percentage points.



United protest: INDIA bloc leaders at Ramlila Maidan in Delhi on Sunday during a rally against alleged electoral irregularities. SHASHI SHEKHAR VISHWAKARMA

Rashtriya Janata Dal leader Tejashwi Yadav said that while Ramlila Maidan was traditionally used to stage the Ramayana, today the Opposition had organised a "Mahabharata for those who steal votes".

Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav described Ramlila Maidan as the "Haldighati of democracy" and said the massive crowd indicated that change was in the offing.

"Those who came to power through U.P. will be ousted from there. And 'U.P. wallahs (people)', who are good at welcoming, are better at giving send-offs," the former Uttar Pradesh Chief Minister said.

Former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee described the SIR exercise as "special intensive relief" for the BJP and said her State has been a victim of it.

"Amit Shah said Narendra Modi is not going anywhere... even if he wants to go, we will not let him. Modi ji and Shah ji, understand this: after Gyanesh Kumar, we will stand against you. Don't forget that for the vote chori (vote theft) you have done, there will be legal action against you," Mr. Gandhi said.

"This is not an ordinary theft; it is not someone stealing something small from a shop... This is a theft of every citizen's voice and expression. In legal parlance, this is called a 'rarest of rare' case; this is called treason," Mr. Gandhi said, alleging that Mr. Modi and Mr. Shah would not have become Prime Minister and Home Minister without Gyanesh Kumar.

Using the metaphor of "Shiv ji ki baraat", where all kinds of creatures are allowed to participate, Mr. Gandhi said India has to be inclusive, where a farmer enjoys the fruits of his labour and where a student studying for 16 hours gets employment. Naming industrialist Gautam Adani, Mr. Gandhi said the Opposition will not allow all resources to be owned by a single person. "The first step to bring the nation back on track is to remove Gyanesh Kumar," he said.

"Narendra Modi ji, Amit Shah ji, Gyanesh Kumar ji, you have attacked the country's soul, our constitution, our democracy; we are not willing to accept this," he said, adding that none of the three is his enemy. He underscored that the voice of every Indian was more important to him than religion.

Speaking the need for a politics of harmony, Mr. Gandhi said: "We have to erase hatred. Narendra Modi, Amit Shah, and the RSS have spread hatred. It is harming the nation and our nation's soul".

The rally was attended by senior Opposition leaders, including Congress president Mallikarjun Kharge, Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi, National Conference patriarch Farooq Abdullah, PDP leader Mehbooba Mufti, CPI(M) general secretary M.A. Baby, CPI general secretary D. Raja, CPI(ML) general secretary Dipankar Bhattacharya, Shiv Sena (UBT)'s Sanjay Raut, NCP (SP)'s Supriya Sule, and others.

SAVING INFILTRATORS: BJP
▸ PAGE 5
RELATED REPORTS ON
▸ PAGE 5

ECI – SIR – वोट चोरी

- BNSS Section 163
- Article 19 (1)
- Article 19 (3)
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- ECI
- CEC – EC's
- SIR
- RPA 1950 – 21(3)
- RPA 1950 – 28 (RER-1960 - 6,7,8)
- RPA 1951 - 29(A)
- Conduct of Election Rules 1961 – 4(A) – Form 26

+ Youtube Comment Box

महत्वपूर्ण तथ्य

Gross GST collections rise 23% to over ₹2.31 lakh cr. in Oct. on festive demand

Press Trust of India
NEW DELHI

Goods and Services Tax collections jumped 23% year-on-year to the second-highest level of over ₹2.31 lakh crore in October as festive buying boosted domestic demand, according to government data released on Sunday.

October is the second consecutive month when monthly gross GST crossed ₹2 lakh crore, and second only to the record of about ₹2.43 lakh crore mop-up in April. The 22.9% year-on-year growth clocked in the month is the fastest recorded pace of gross mop-up in the fiscal year. Gross GST collections from domestic sales rose 16% to over ₹1.59 lakh crore, and revenues from imports climbed 42% to ₹72,246 crore.



October is the second straight month when monthly gross GST crossed ₹2 lakh crore.

The ₹2.31 lakh crore collection includes Central GST mop-up of 42,935 crore, State GST of ₹51,340 crore and Integrated GST of over ₹1.37 lakh crore, data showed. GST refunds increased 6.5% year-on-year to ₹27,934 crore in October. After adjusting for refunds, net GST collections rose 26% to over ₹2.03 lakh crore in October.

In April-October, gross GST collection grew 13.2% to over ₹14.77 lakh crore. Net collections rose 13% to over ₹12.69 lakh crore.

Manoj Mishra, Grant Thornton Bharat, Partner and Tax Controversy Management Leader, said October collections capture the festive-season demand cycle, which typically brings higher consumer spending, retail activity and movement of goods across sectors.

"The focus now should be on sustaining domestic revenue growth and ensuring that the benefits of GST 2.0 translate into stronger compliance, smoother input tax credit flows and faster refunds for businesses," Mr. Mishra said.

EY India Tax Partner, Saurabh Agarwal, said the GST collections reflect the continued resilience of the Indian economy despite global headwinds.

GST Collection
1 October
GST Collection
2.31 लाख करोड़
23%
April-2026
2.43 Lakh
GST
2016
1 July-2017
279-A
GST Council

YouTube Homework

Monthly
Import / Export
2 Months
RBI
MPC
CPI
WPI
PPI
IIP
ICI
ISP
External Sector

महत्वपूर्ण तथ्य

Andhra braces for second cyclone within a week; five districts placed on red alert

Nellore Sravani
VIJAYAWADA



Calm before the storm: The cyclone is likely to bring heavy rain to Tamil Nadu and Odisha as well. (K VEJAYANAND RAJ)

Barely a week after being battered by "very severe" Cyclone Arnab, Andhra Pradesh is bracing for Cyclone Murasu, expected to make landfall on Tuesday, with five districts put on red alert.

The weather system over the Bay of Bengal intensified into a cyclonic storm and was centred at around 350 km east of Chennai on Sunday night.

The storm, which is likely to bring heavy rainfall to several Tamil Nadu districts as well, is expected to move west northwestward and intensify into a severe cyclonic storm by Monday morning.

Between Monday night and early hours of Tuesday, it is likely to cross into Andhra Pradesh with wind speeds gusting up to 120 km per hour between Nellore and Narsapur.

Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu, who cancelled his visit to Delhi, held a review meeting on Sunday and directed officials to step up preparedness to tackle the possible impact of the storm. Odisha, which experienced multiple landslides during Cyclone Arnab, is also bracing for the impact of Murasu, with authorities saying southern districts were likely to receive heavy rainfall.

Cyclone Murasu comes at a time when Andhra Pradesh is just beginning to recover from the impact of Cyclone Arnab, a storm that killed five people and submerged crops in more than 3.5 lakh hectares of land. It also damaged about 2,425 km of roads and brought down some 15,000 electric poles. The State government puts its losses at ₹4,600 crore, and officials now have little time to prepare for the next storm.

As many as 1,088 medical teams and 116 relief camps have been prepared in Andhra Pradesh districts likely to be affected by the latest cyclone, the Chief Minister's office said in a post on X.

Red alert

While it was the northern part of Andhra Pradesh that bore the brunt last week, this time, the central and southern coastal parts of the State are likely to be affected, according to the Andhra Pradesh State Disaster Management Authority.

The IMD has put five districts in the State – SPSR Nellore, Prakasam, Guntur, Bapatla, and Krishna – on red alert for November 2.

In Tamil Nadu, for the 24-hour period from 8.30 a.m. on Monday, heavy to very heavy rain is likely at isolated places over Chennai and Tiruvallur districts. Heavy rain is also likely at isolated places over Chengalpattu, Kancheepuram, Ranipet, Vellore and Nilgiris districts.

In Odisha, the State government has identified 150 landslide-prone locations in Gajapati district alone. During Cyclone Arnab, five people were killed in separate landslides in the State.

Addressing a press conference, Special Relief Commissioner Rajesh Prabhakar Patil warned that the situation could worsen as the ground was already saturated and heavy rain was forecast in southern Odisha. "We have directed district collectors to evacuate people from vulnerable areas," he said.

(With inputs from Deepu Ramakrishnan in Chennai and Satyasundar Barik in Bhubaneswar)

पक्षवात प्रस्तुत

YouTube Homework

- Cyclone Arnab

महत्वपूर्ण तथ्य

चक्रवात मुरासु (Cyclone Murasu)

- चक्रवात का प्रकार: यह एक गंभीर चक्रवाती तूफान (Severe Cyclonic Storm) है। तट पार करते समय इसकी हवाओं की गति 100 से 110 किमी/घंटा और अधिकतम 120 किमी/घंटा तक रहने का अनुमान है।
- उत्पत्ति और घोषणा: बंगाल की खाड़ी के गहरे दबाव से यह तूफान 1 नवंबर 2026 को विकसित हुआ, जिसके बाद मौसम विभाग (IMD) ने इसके नाम और खतरे की आधिकारिक घोषणा की।
- तट से टकराने का समय: मौसम विज्ञानियों के अनुसार यह चक्रवात 2 नवंबर की रात से 3 नवंबर 2026 की सुबह के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट (ओंगोल और नेल्लोर के पास) से टकराएगा।
- नामकरण और अर्थ: इस तूफान का नाम भारत ने रखा है। 'मुरासु' एक तमिल शब्द है जिसका मतलब "युद्ध का नगाड़ा या ढोल" (War Drum) होता है।

संभावित नुकसान और असर:

- आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों (नेल्लोर, प्रकाशम, गुंटूर, कृष्णा) में अत्यधिक भारी बारिश और अचानक बाढ़ का खतरा है।
- तेज हवाओं के कारण कच्चे घर, बिजली के पोल, मोबाइल टावर और पेड़ गिरने से संचार और बिजली व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
- लगातार हो रही बारिश से धान और व्यापारिक फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका है।
- समुद्र में ऊंची लहरें उठने के कारण तटीय इलाकों के डूबने का खतरा है, इसलिए मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी दी गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य

Opposition flays BJP day after Independent MLCs 'join' ruling party in Bihar

Tejashwi seeks disqualification of Bansidhar Brajwasi, Rahul Raj; row comes a day after BJP issued statement welcoming the two to the party; hour later, it said the MLCs had 'extended support' to it

Amit Bhelari
PATNA

A day after two recently elected Independent Members of the Bihar Legislative Council – Bansidhar Brajwasi and Rahul Raj – "joined" the ruling Bharatiya Janata Party (BJP), the Opposition on Sunday demanded that both be disqualified under the anti-defection law.

In the results declared last week, Mr. Brajwasi defeated Janata Dal (United)'s Abhishek Jha from Tirhut Graduates' seat while Rahul Raj defeated JD(U)'s Anand Pushkar from Saran Teachers' seat.

Around 8 p.m. on Saturday, the BJP issued a release welcoming the two legislators to the party.

Subsequently, in a media interaction, Mr. Brajwasi said, "I have joined the BJP after Chief Minister Samrat Choudharyji gave me an assurance that teachers' concerns would be resolved if we work together." However, nearly an hour later, the BJP issued another press note stating, "Newly elected Legislative Council members Bansidhar Brajwasi and Rahul Raj have extended their support" to it.



RJD MP Manoj Kumar Jha said the party will urge the Acting Chairman of the Legislative Council to take action against the two MLCs. ANI

Soon after, the Tirhut Graduates' MLC put out a video on Facebook, where he said, "I have not joined BJP. I have just offered support. I don't know why people are making a hue and cry about it." There was no comment from Mr. Raj.

On Sunday, Leader of the Opposition in the Assembly and Rashtriya Janata Dal (RJD) working president Tejashwi Yadav accused the MLCs of violating the anti-defection law and hit out at the BJP for "making a mockery of the Constitution".

RJD MP Manoj Kumar Jha said under the Constitution's Tenth Schedule, those elected as Independents are liable to be disqualified upon joining any party. He added that the RJD will meet Acting Chairman of the Legislative Council Ram Bachan Rai over the issue. "If he fails to take an immediate and impartial decision, we'll raise the matter before the court of law, as well as the court of people," Mr. Jha said.

Cong. takes potshots

The Congress took potshots at the BJP, accusing it of "backstabbing its coalition partner JD(U)". "The BJP has been calling the INDIA bloc a divided house. But how it conspired to ensure the defeat of its own ally is now for all to see," said Congress spokesperson Asit Nath Tiwari.

Prashant Kishor-led Jan Suraaj Party, which also bagged a seat in the MLC polls, termed the episode a "cruel and vulgar joke".

Of the eight seats that went to the polls, ruling National Democratic Alliance partners BJP and JD(U) contested four each. While the BJP won two, the JD(U) bagged one. Two seats were won by the RJD.

YouTube Homework

- Other Schedules

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची (10th Schedule) को आमतौर पर 'दल-बदल विरोधी कानून' (Anti-Defection Law) के नाम से जाना जाता है। इसे 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक लाभ के लिए एक दल से दूसरे दल में शामिल होने वाले विधायकों और सांसदों के दलबदल को रोकना और सरकारों में स्थिरता लाना है।

दसवीं अनुसूची के प्रमुख प्रावधान विस्तार से निम्नलिखित हैं:

1. अयोग्यता के आधार (Grounds for Disqualification)

- किसी सदस्य को निम्नलिखित स्थितियों में दलबदल का दोषी माना जाता है और वह सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है:
- स्वेच्छा से इस्तीफा: यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है।
- व्हिप (Whip) का उल्लंघन: यदि कोई सदस्य अपने राजनीतिक दल के निर्देशों (व्हिप) के विपरीत सदन में मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है, और पार्टी 15 दिनों के भीतर उसकी इस हरकत को माफ नहीं करती है।
- निर्दलीय सदस्य: यदि कोई निर्दलीय चुना गया सदस्य (बिना किसी पार्टी के) चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
- मनोनीत सदस्य (Nominated Member): यदि कोई मनोनीत सदस्य (जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा नियुक्त) अपनी नियुक्ति के 6 महीने बीत जाने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है।

2. अपवाद (Exceptions - कब अयोग्यता लागू नहीं होती)

- इस कानून में कुछ विशेष परिस्थितियाँ दी गई हैं जहाँ सदस्य अयोग्य नहीं ठहरते:
- पार्टियों का विलय (Merger): यदि किसी राजनीतिक दल के कम से कम दो-तिहाई (2/3) सदस्य किसी अन्य दल में विलय (merge) करने का निर्णय लेते हैं, तो वे अयोग्य नहीं माने जाते।
- अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनने पर: यदि कोई सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष (Speaker), राज्यसभा का उपसभापति, या विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाता है और वह निष्पक्ष रहने के लिए अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देता है, तो उसकी सदस्यता रद्द नहीं होती। पद छोड़ने के बाद वह फिर से अपनी पार्टी में लौट सकता है।

3. निर्णय लेने का अधिकार (Deciding Authority)

- दलबदल के आधार पर किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने का अंतिम निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी यानी अध्यक्ष (Speaker) या सभापति (Chairman) का होता है।
- शुरुआत में इस कानून में कहा गया था कि अध्यक्ष का फैसला अंतिम होगा और उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन 1992 में सर्वोच्च न्यायालय (Kihoto Hollohan केस) ने यह व्यवस्था दी कि अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की जा सकती है, यानी उसके फैसले के खिलाफ कोर्ट जाया जा सकता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

4. कानून के लाभ

- स्थिरता: यह सांसदों और विधायकों के बार-बार दल बदलने (आया राम, गया राम की राजनीति) पर रोक लगाकर सरकारों को स्थिरता देता है।
- जनादेश का सम्मान: यह मतदाताओं के साथ होने वाले धोखे को रोकता है, क्योंकि मतदाता उम्मीदवार को एक निश्चित पार्टी की विचारधारा के आधार पर चुनते हैं।
- अनुशासन: यह राजनीतिक दलों में अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है।

5. चुनौतियाँ या कमियाँ

- लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर असर: इस कानून के कारण सांसद या विधायक दल की नीतियों के खिलाफ अपनी व्यक्तिगत राय नहीं रख पाते, भले ही वे जनता के हित में हों।
- अध्यक्ष की भूमिका: कई बार सदन के अध्यक्ष राजनीतिक दबाव या पक्षपात के कारण दलबदल के मामलों में निर्णय लेने में बहुत देरी करते हैं।

UPSC - Prelim

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: (वर्ष 2025)

1. यदि यह प्रश्न उठता है कि लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निरर्हता (disqualification) से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो संघीय मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होता है।
2. भारत के संविधान में 'राजनीतिक दल' शब्द का कोई उल्लेख नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

महत्वपूर्ण तथ्य



Celebrating culture: Folk artistes get ready to perform at an event celebrating Tamil Nadu Day on Sunday. ☐ ZUHAIB SATHIKADO

TVK-led government observes November 1 as Tamil Nadu Day

The Hindu Bureau
CHENNAI

The Tamil Nadu government on Sunday celebrated Tamil Nadu Day, with Governor Rajendra Vishwanath Arlekar and Chief Minister C. Joseph Vijay extending their greetings.

Mr. Vijay said the State's unique features and historical greatness should be celebrated on the day it was formed on linguistic lines. In a social media message, he said the history of those who fought for the merger of Tamil-speaking areas with Tamil Nadu and protected the Tamil language would serve as a guide for Tamil unity and the protection of its rights. "Let us pledge to protect the art and culture of Tamils and make Mother Tamil proud," he said.

In Chennai, the government organised various folk and cultural events at public places to celebrate the day. Besides, several Ministers, including Minister for Tamil Development Rajmohan, participated in an official function to mark the day. Mr. Arlekar organised a function at Lok Bhavan to mark the occasion.

DMK takes exception

However, the DMK, the Principal Opposition party, took exception to the celebrations, contending that Tamil Nadu Day fell on July 18 while November 1 marked the reorganisation of States on linguistic lines and was an occasion to remember the martyrs who fought for the merger of Tamil-speaking areas with Tamil Nadu. In a statement, the DMK headquarters said November 1 was certainly a day deserving of celebration, but it could not be celebrated as Tamil Nadu Day.

"These boundary struggles were not merely about territory. They were struggles for linguistic rights, identity and the will of the people. November 1 is a historically significant day to remember with gratitude those who laid down their lives, went to prison, and dedicated their lives to these struggles. It is the day to commemorate the martyrs of the boundary movements," it said.

18 July - TN - Day

TN Day - 1 Nov''

YouTube Homework

- **Formation of State in india**

महत्वपूर्ण तथ्य

1. संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions)

- **अनुच्छेद 1 (Article 1):** भारत (इंडिया) को **'राज्यों का संघ' (Union of States)** घोषित करता है।
- **अनुच्छेद 3 (Article 3):** संसद को नए राज्यों का निर्माण करने, किसी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाने/घटाने या किसी राज्य के नाम व सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार देता है।
- **अनुच्छेद 4 (Article 4):** इसके तहत किया गया बदलाव संविधान संशोधन (Article 368) नहीं माना जाता है।

2. स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक स्थिति (1950)

- 1950 में भारतीय संविधान लागू होने पर राज्यों को **4 भागों (Part A, B, C, D)** में बाँटा गया था:
- **Part A:** पूर्व ब्रिटिश प्रांत (जैसे- बॉम्बे, मद्रास, उत्तर प्रदेश)।
- **Part B:** रियासतों के संघ (जैसे- हैदराबाद, मायसोर)।
- **Part C:** मुख्य आयुक्त के प्रांत (जैसे- दिल्ली, अजमेर)।
- **Part D:** अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।

3. भाषाई पुनर्गठन आयोग और समितियाँ (Commissions)

- **धर आयोग (Dhar Commission, 1948):**
  - अध्यक्ष: एस.के. धर।
  - **सिफारिश:** राज्यों का पुनर्गठन भाषा के बजाय **प्रशासनिक सुविधा** के आधार पर होना चाहिए।
- **JVP समिति (1948-49):**
  - सदस्य: जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, पट्टाभि सीतारमैया।
  - **सिफारिश:** भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को तुरंत अस्वीकार कर दिया।
- **पहला भाषाई राज्य (1953):**
  - पोट्टी श्रीरामुलु के 56 दिनों के आमरण अनशन और निधन के बाद भारी जनआंदोलन हुआ।
  - इसके फलस्वरूप 1953 में मद्रास से अलग करके **आंध्र प्रदेश** को पहला भाषाई राज्य बनाया गया।
- **फज़ल अली आयोग / राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC, 1953):**
  - अध्यक्ष: फज़ल अली (सदस्य: के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंज़रू)।
  - **सिफारिश:** 'एक भाषा-एक राज्य' का सिद्धांत खारिज किया, लेकिन भाषा को मुख्य आधार स्वीकार किया।
  - **परिणाम: राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956** और **7वां संविधान संशोधन (1956)** पारित कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश (UTs) बनाए गए।

महत्वपूर्ण तथ्य

4. 1956 के बाद नए राज्यों के गठन की क्रोनोलॉजी (Chronology)

वर्ष	नया राज्य/क्षेत्र	किससे अलग/बदलाव हुआ	क्रम
1960	**गुजरात और महाराष्ट्र**	बॉम्बे राज्य का विभाजन (गुजराती व मराठी भाषाई आधार)	15वां राज्य (गुजरात)
1963	**नागालैंड**	असम के नागा पहाड़ी क्षेत्रों को अलग करके	16वां राज्य
1966	**हरियाणा** (और चंडीगढ़ UT)	पंजाब से हिंदी भाषी क्षेत्र अलग किया गया	17वां राज्य
1971	**हिमाचल प्रदेश**	केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा	18वां राज्य
1972	**मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय**	UTs से पूर्ण राज्य बनाए गए (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन)	19, 20 और 21वें राज्य
1975	**सिक्किम**	36वें संविधान संशोधन द्वारा भारत का पूर्ण राज्य बना	22वां राज्य
1987	**मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा**	केंद्र शासित प्रदेशों से पूर्ण राज्य बने	23, 24 और 25वें राज्य
2000	**छत्तीसगढ़** (1 नव.), **उत्तराखंड** (9 नव.), **झारखंड** (15 नव.)	क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से विभाजित	26, 27 और 28वें राज्य
2014	**तेलंगाना** (2 जून)	आंध्र प्रदेश से अलग किया गया	29वां राज्य (उस समय)
2019	**जम्मू-कश्मीर और लद्दाख**	J&K पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा दो नए UTs में विभाजन	

महत्वपूर्ण तथ्य

Navy to launch ₹80,000-cr. warship project – Project-18.A

Saurabh Trivedi
NEW DELHI

The government has given a major push to the Indian Navy's next-generation destroyer programme amid the growing maritime security challenges posed by China and Pakistan, both of which are strengthening their own underwater warfare capabilities.

The Defence Acquisition Council (DAC), chaired by Defence Minister Rajnath Singh, had recently accorded in-principle approval to futuristic warships under Project 18A.

The delivery of the warships is expected to begin five to 10 years after the contract is signed, given the complexity and scale of the programme.

A senior Defence Ministry official confirmed the development.

The proposed programme, estimated to cost around ₹80,000 crore, aims to develop a new generation of stealth-guided missile destroyers equipped with advanced weapons, sensors, and technologies, the official said.

The warships are expected to have nearly 75% indigenous content, with both defence public sector undertakings (DPSUs) and private sector companies eligible to participate in the competitive bidding process, the official added.

The programme assumes significance as China continues to expand its naval presence in the Indian Ocean Region and enhance its submarine fleet, while Pakistan is also strengthening its underwater warfare capabilities with the induction of advanced submarines.

The evolving security environment has underscored the need for India to strengthen its surface combat fleet and maintain a credible maritime deterrence across the Indian Ocean Region.



The next-generation destroyers are expected to substantially enhance multi-domain combat capabilities. REUTERS

Futuristic capabilities

Several existing destroyers of the Indian Navy are due for decommissioning in coming years, making the induction of advanced frontline surface combatants essential to maintaining the fleet's operational strength, the official added.

The futuristic destroyers, to be designed by the Navy's Warship Design Bureau, are expected to feature significantly more advanced systems than the Visakhapatnam-class destroyers.

These warships are likely to have enhanced firepower, sophisticated surveillance sensors, improved air defence systems, and advanced anti-submarine warfare capabilities, providing the Navy with greater operational flexibility against emerging maritime threats.

The Indian Navy currently operates around 12 or 13 relatively new guided-missile destroyers, which form the backbone of its surface combat fleet and provide capabilities across air defence, anti-surface warfare, and anti-submarine operations.

These include the Visakhapatnam-class, Kolkata-class, and Delhi-class destroyers.

The existing warships are equipped with an array of advanced weapon systems, including BrahMos supersonic cruise missiles, surface-to-air missiles, naval guns, close-in weapon systems, and anti-submarine warfare equipment.

महत्वपूर्ण तथ्य

- **प्रोजेक्ट 18ए (Project 18A / Project 18-class Destroyer)** भारतीय नौसेना की भविष्य की **अगली पीढ़ी के विध्वंसक (Next Generation Destroyers - NGD)** पोतों के निर्माण की एक अत्यधिक महत्वाकांक्षी और बड़ी परियोजना है।
- इस परियोजना से जुड़ी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:
- **रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की मंजूरी:**
    - रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने भारतीय नौसेना के लिए **₹75,000 करोड़** से अधिक की लागत वाले इस **प्रोजेक्ट 18ए (P-18A)** विध्वंसक पोत प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक (In-principle) मंजूरी प्रदान की है।
- **प्रमुख विशेषताएँ और आकार (Size & Characteristics):**
    - यह वर्तमान में मौजूद विध्वंसकों (जैसे कोलकाता-श्रेणी और विशाखापत्तनम-श्रेणी) की तुलना में आकार में काफी बड़े और उन्नत **स्टील्थ गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर (Stealth Guided-Missile Destroyers)** होंगे।
    - इन जहाजों का मानक विस्थापन (Standard Displacement) लगभग 10,000 टन और पूर्ण भार (Full Load) पर 14,000 से 15,000 टन के आसपास होने की योजना है।
    - इनकी लंबाई लगभग 180 मीटर होगी।
- **उन्नत हथियार प्रणालियाँ (Advanced Armament):**
- इन युद्धपोतों में अत्यधिक घातक और आधुनिक हथियार प्रणालियों को शामिल किए जाने की योजना है। इसमें बड़ी संख्या में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम (VLS) सेल होंगे, जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों (जैसे ब्रह्मोस-ईआर, सुपरसोनिक/हाइपरसोनिक संस्करण) और पनडुब्बी रोधी स्मार्ट (SMART) मिसाइलों को दागने में सक्षम होंगे।
- इनमें उन्नत सक्रिय और निष्क्रिय ऐरे सोनार, अत्याधुनिक AESA/PESA रडार और अगली पीढ़ी की रक्षा प्रणालियाँ शामिल होंगी।
- **इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन (IEP):**
- इन मेगा जहाजों को शक्ति देने के लिए आधुनिक **इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन (IEP)** तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जो इनकी ऊर्जा और संचालन क्षमता को अत्यधिक मजबूत बनाएगी।
- **आत्मनिर्भर भारत और रणनीतिक महत्व:**
- यह प्रोजेक्ट भारत की **'आत्मनिर्भर भारत'** पहल के साथ पूरी तरह संरेखित है, जिसमें घरेलू रक्षा विनिर्माण और स्वदेशी शिपबिल्डिंग क्षमताओं को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
- यह परियोजना हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और नौसेना की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी।

महत्वपूर्ण तथ्य

- हाल के महीनों (जून से अक्टूबर 2026) में भारतीय नौसेना (Indian Navy) अपनी ताकत बढ़ाने और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत कई अत्याधुनिक स्वदेशी युद्धपोतों (INS) को शामिल करने और विशेष रक्षा उपकरणों की खरीद को लेकर काफी चर्चा में रही है।

- इन महीनों में चर्चा में रहे मुख्य INS और खरीदे गए विशेष रक्षा उपकरणों की सूची नीचे दी गई है:

चर्चा में रहे प्रमुख INS (युद्धपोत)

- INS दुनागिरी (INS Dunagiri): जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश को समर्पित किया। यह प्रोजेक्ट 17A का पांचवा अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट (Stealth Frigate) है, जो ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (MR-SAM) प्रणाली से लैस है।
- INS संशोधक (INS Sanshodhak): इसे भी जून में नौसेना में शामिल किया गया। यह एक बड़ा सर्वेक्षण पोत (Survey Vessel) है, जो गहरे समुद्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और निगरानी के लिए AUV (ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल) और ROV तकनीकों से लैस है।
- INS अग्रय (INS Agray): यह अर्नाला-क्लास का पनडुब्बी रोधी युद्धपोत (Anti-Submarine Warfare Craft) है, जिसे जून में तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए शामिल किया गया। यह हल्के टॉरपीडो और रॉकेट लॉन्चर से लैस है।
- INS समर्थक (INS Samarthak): अक्टूबर 2026 में भारतीय नौसेना ने एलएंडटी (L&T) द्वारा निर्मित इस स्वदेशी बहुउद्देशीय युद्धपोत (Multi-Purpose Warship) को कमीशन किया। यह समुद्री निगरानी, हथियार परीक्षण और मानव रहित प्रणालियों (Drones) के संचालन में सहयोग करेगा।
- INS विक्रांत (INS Vikrant): अक्टूबर 2026 के अंत में भारत के इस पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत (Aircraft Carrier) पर पहली बार फ्रांसीसी राफेल मरीन (Rafale Marine) फाइटर जेट की सफल लैंडिंग कराई गई, जिसके कारण यह वैश्विक स्तर पर चर्चा में रहा।

खरीदे गए और स्वीकृत हुए विशेष सैन्य उपकरण / सौदे

- अक्टूबर 2026 में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) ने नौसेना के लिए कई बड़े सौदों को मंजूरी दी:
- 1. 8 नेक्स्ट-जनरेशन कार्वेट (Next-Generation Corvettes): अक्टूबर के अंत में CCS ने ₹40,000 करोड़ से अधिक के मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, जिसके तहत भारतीय नौसेना के लिए 8 नए कॉम्पैक्ट, तेज और स्टील्थ युद्धपोत (कार्वेट) बनाए जाएंगे। इनका निर्माण गार्डन रीच शिपबिल्डर्स (GRSE) और गोवा शिपयार्ड द्वारा किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

- 2. एक्टिव ऑफबोर्ड डिकॉय सिस्टम (Active Offboard Decoy Systems - AODS): अक्टूबर में रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के युद्धपोतों को दुश्मन की आधुनिक एंटी-शिप मिसाइलों के हमलों से बचाने के लिए इस एडवांस मिसाइल काउंटरमेजर सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी।
- 3. ECGNSS जैमर तकनीक (ECGNSS Jammers): युद्धपोतों को हवाई हमलों, दुश्मन के ड्रोन और गाइडेड मिसाइलों से बचाने के लिए ₹449 करोड़ के स्वदेशी जैमर का सौदा किया गया। यह प्रणाली दुश्मन के सैटेलाइट नेविगेशन (GNSS) को पूरी तरह भ्रमित कर उनका रास्ता भटका सकती है।
- 4. स्वदेशी कंप्रेसर और प्रोपल्शन पार्ट्स: नौसेना ने अपनी विदेशी निर्भरता खत्म करने के लिए घरेलू स्टार्टअप्स और MSMEs के साथ ₹1,950 करोड़ से अधिक के सौदे किए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

WHAT IS IT?

Hell chicken: a fruity dino

Vasudevan Mukunth

Flowering plants evolved during the Cretaceous period (145-66 million years ago) and radically changed terrestrial ecosystems. Did this affect the dinosaurs as well? A new study in *Nature Communications* has answered in the affirmative, based on a small, bird-like dinosaur from the Hell Creek Formation in North America its authors found.

The species is a previously unknown member of the caenagnathids — toothless theropod dinosaurs belonging to the oviraptorosaurs.

The fossil described in the study, dubbed *Infernogallus jamesi*, had a nearly complete skull. The team estimated the animal was an adult when it died and weighed around 12 kg. 'Infernogallus' means 'hell chicken'.

CT scans and reconstructions of the jaw muscles revealed an unusual feeding apparatus. Unlike most non-avian theropods, whose jaws moved up and down, *I. jamesi* could slide its lower jaw forwards and backwards by up to 1.5 cm. Its jaw muscles also seemed to favour this motion rather than developing a strong downward bite.

As a result, the team figured that tough, fibrous vegetation or hard seeds couldn't have been an important part of the *I. jamesi* died. Instead, the researchers found the closest likeness in its jaw's motion to be among the Pesquet's parrots in New Guinea, which strip fruit pulp from seeds and chew the soft flesh in its mouth.



The species is a previously unknown member of the caenagnathids. DANIELLE DUFAULT

Thus, they have hypothesised *I. jamesi* ate lots of fleshy fruits and other soft plant tissues.

Prior research has found that the caenagnathids originated shortly after flowering plants began producing fruits, and their more elaborate feeding adaptations broadly coincided with when the fruits became bigger and more diverse.

For feedback and suggestions
for 'Science', please write to **science@thehindu.co.in** with the subject 'Daily page'

महत्वपूर्ण तथ्य

नरक की मुर्गी: एक फल खाने वाला डायनासोर (Hell chicken: a fruity dino)

- **मुख्य बातें**
- **नया डायनासोर:** उत्तर अमेरिका के हेल क्रीक फॉर्मेशन (Hell Creek Formation) में पक्षी जैसा एक छोटा डायनासोर पाया गया है, जिसका नाम ***Infernogallus jamesi*** रखा गया है। 'इनफर्नोगैलस' का शाब्दिक अर्थ **'हेल चिकन' (Hell chicken / नरक की मुर्गी)** होता है।
- **शारीरिक बनावट:** यह लगभग 12 किलोग्राम वजन का एक वयस्क डायनासोर था, जो बिना दांत वाले थेरोपोड (caenagnathids / oviraptorosaurs) समूह से संबंधित था।
- **विशेष जबड़ा (Feeding Mechanism):** अधिकांश थेरोपोड डायनासोरों के विपरीत, जिनका जबड़ा केवल ऊपर-नीचे होता था, *I. jamesi* का निचला जबड़ा **1.5 सेमी तक आगे-पीछे** खिसक सकता था।
- **खान-पान की आदतें:** जबड़े की इस अनोखी गति की तुलना न्यू गिनी के **पेस्क्वेट तोते (Pesquet's parrot)** से की गई है, जो फलों के गूदे को बीजों से अलग करके खाते हैं।
- **निष्कर्ष:** शोधकर्ताओं का मानना है कि यह डायनासोर कड़े बीजों या सख्त वनस्पतियों के बजाय **गूदेदार फल और नरम पौधे** खाता था। इसका विकास क्रेटेशियस काल (Cretaceous period) में फूलों वाले पौधों और बड़े फलों की उत्पत्ति के साथ हुआ था।

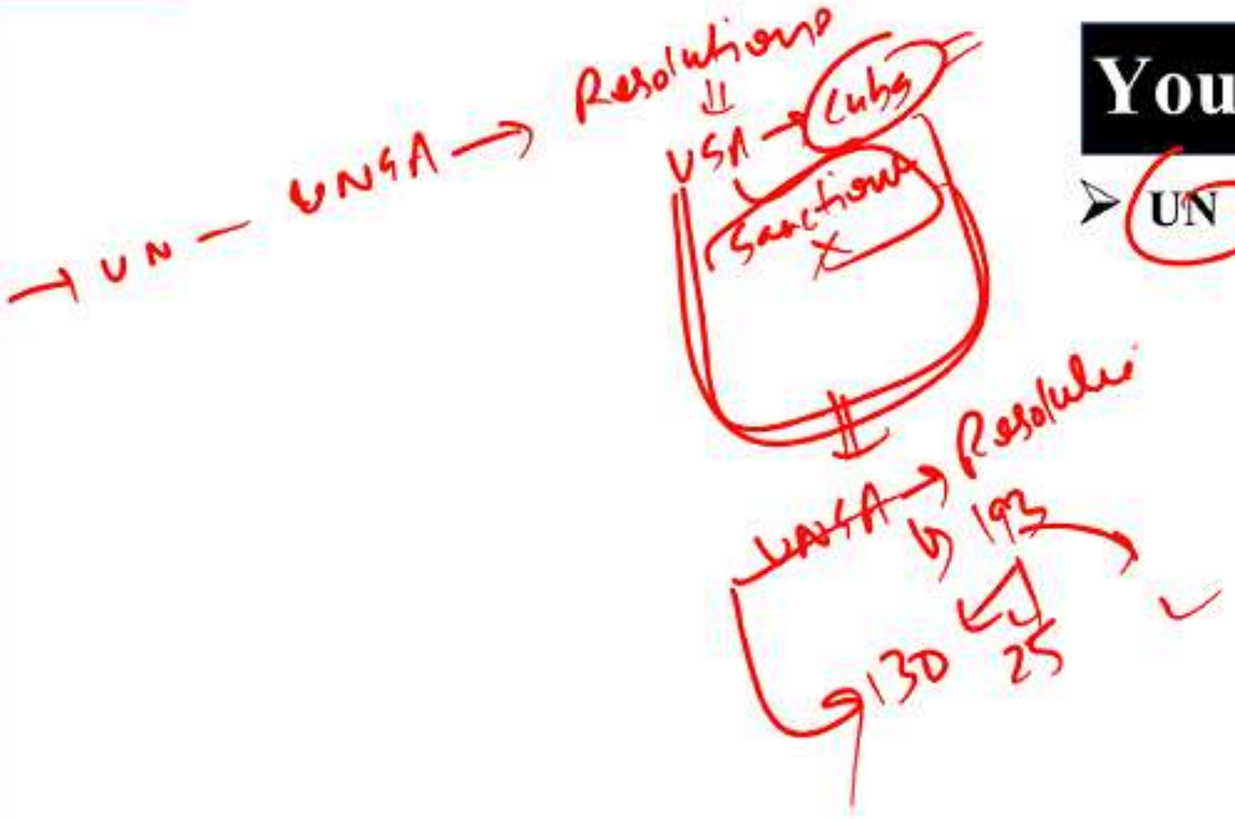
महत्वपूर्ण तथ्य

Dwindling support

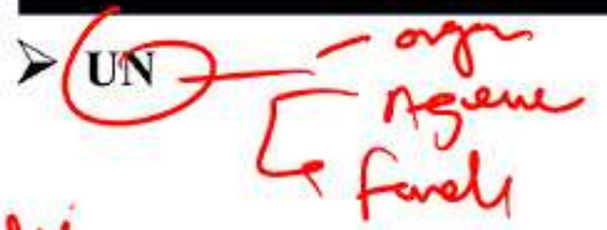
India and the world must stand up against the bullying of Cuba by the U.S.

Nearly every year since 1992, the United Nations General Assembly has passed a resolution calling on the U.S. to end its decades-old economic embargo on Cuba. As a result, the outcome at the UNGA resolution titled the 'Necessity of ending the economic, commercial and financial embargo imposed by the United States of America against Cuba' passed on October 30, was expected. Surprisingly, the support for the resolution this year was dramatically lower than previous years. During the preceding decade, more than 180 countries of the 193-member UN GA had expressed their support for ending the embargo, but the numbers dropped to 165 in favour in 2025; this year's tally dropped sharply lower, with 130 in favour, 25 abstaining and 17 countries voting against the resolution. The trend clearly points to efforts by the Trump administration to use its pressure on countries to change their votes, and many appear to have succumbed to those threats. Among those were several Latin American countries, that have more recently grown closer to the U.S., particularly after the operation in Venezuela in January 2026, where U.S. marines abducted President Maduro and brought him to the U.S. for a trial. Countries in the region such as Costa Rica, Ecuador, Argentina, and Colombia that have downgraded ties with Havana, switched votes on the resolution. In addition, U.S. diplomats argued that Havana-Moscow ties emboldened Russia's war in Ukraine, which led to several western countries switching their vote. Diplomats from Ukraine and Poland, for example, referred to Cuba's ties with Russia while explaining their vote, and Germany and Italy switched for the first time in many years to abstaining on the resolution. While it is clear that the bulk of the Group of 77 and non-aligned states including India maintained their support on the resolution for Cuba, the vote by the others demonstrates a disquieting turn.

Amidst these turns, New Delhi must be credited for standing firm on the issue, opposing the embargo, and calling for "dialogue and diplomacy" in its statement. The vote came a month after the BRICS New Delhi declaration expressed "deep concern" over the tightening of unilateral blockade measures on Cuba, and the "worrying humanitarian impact" on the Cuban people. It is important that India continue to stand up to such unilateral measures and amplify the voice of smaller countries, particularly those in the Global South.



YouTube Homework



महत्वपूर्ण तथ्य

भारत और दुनिया को अमेरिका द्वारा क्यूबा पर की जा रही धौंस-पट्टी के खिलाफ खड़ा होना चाहिए।

- **यूएनजीए (UNGA) प्रस्ताव:** 1992 से लगभग हर साल, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने अमेरिका से क्यूबा पर अपने दशकों पुराने आर्थिक प्रतिबंधों को समाप्त करने का आह्वान करते हुए प्रस्ताव पारित किया है। 30 अक्टूबर को पारित हुए इस प्रस्ताव के परिणाम की उम्मीद थी, लेकिन इस वर्ष समर्थन पिछले वर्षों की तुलना में नाटकीय रूप से कम हो गया।
- **समर्थन में भारी गिरावट:** पिछले दशक में 193 सदस्यीय यूएनजीए के 180 से अधिक देश प्रतिबंध समाप्त करने का समर्थन करते थे, जो 2025 में घटकर 165 रह गया था; और इस साल यह संख्या गिरकर पक्ष में 130, अनुपस्थित 25 और विरोध में 17 देशों तक आ गई।
- **अमेरिकी दबाव और लैटिन अमेरिकी देशों का रुख:** यह गिरावट ट्रंप प्रशासन के उस दबाव को दर्शाती है जिसके तहत देशों के वोट बदले गए। वेनेजुएला में जनवरी 2026 के बाद (जहां अमेरिकी सेना द्वारा राष्ट्रपति मादुरो को हटाकर अमेरिका लाया गया था), कई लैटिन अमेरिकी देश अमेरिका के करीब आ गए हैं। कोस्टा रिका, इक्वाडोर, अर्जेंटीना और कोलंबिया जैसे देशों ने हवाना (क्यूबा) से अपने संबंध कम कर दिए और इस प्रस्ताव पर अपना वोट बदल लिया।
- **पश्चिमी देशों का रुख:** इसके अलावा, अमेरिका ने तर्क दिया कि हवाना और मास्को के संबंधों ने यूक्रेन में रूस के युद्ध को बढ़ावा दिया, जिससे कई पश्चिमी देशों (जैसे यूक्रेन, पोलैंड, जर्मनी और इटली) ने अपना वोट बदल लिया या मतदान से दूरी बना ली। हालांकि, भारत सहित जी-77 (Group of 77) और गुटनिरपेक्ष देशों ने क्यूबा के प्रस्ताव का अपना समर्थन जारी रखा।
- **भारत की भूमिका:** इस सबके बीच, नई दिल्ली को इस मुद्दे पर अडिग रहने, प्रतिबंध का विरोध करने और अपने बयान में "बातचीत और कूटनीति" की वकालत करने के लिए सराहना मिलनी चाहिए। यह वोट ब्रिक्स (BRICS) नई दिल्ली घोषणा के एक महीने बाद आया है, जिसमें क्यूबा पर एकतरफा नाकाबंदी और उसके मानवीय प्रभाव पर गहरी चिंता व्यक्त की गई थी। भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह ऐसे एकतरफा उपायों के खिलाफ खड़ा होता रहे और ग्लोबल साउथ (Global South) के छोटे देशों की आवाज़ को बुलंद करता रहे।

महत्वपूर्ण तथ्य

Bhutan builds 108 stupas in 9 hours, dedicates Chorten no. 76 to Modi

Rahul Karmakar
GELEPHU (BHUTAN)

Bhutan King Jigme Khesar Namgyel Wangchuk on Sunday dedicated one of the 108 Buddhist stupas erected in a nine-hour construction feat to Prime Minister Narendra Modi as a mark of appreciation for India's support for the country's ambitious Gelephu Mindfulness City (GMC) project.

About 40,000 trained volunteers built the 108 Jangchub Chortens in what could be a potentially record-breaking royal initiative to lay the spiritual foundation of the planned city.



Bhutan dedicated Chorten no. 76 to Prime Minister Narendra Modi for India's support to the Gelephu project. RAHUL KARMAKAR

Spiritual City

About 240 km south-southeast of Bhutan's capital, Thimphu, Gelephu borders Assam's Chirang district. King Wangchuk envisions the city as a spirituality-driven global economic hub.

The King, other members of the royal family, top officials and foreign dignitaries faced Chorten Number 79 from the ceremonial ground as thousands of people around chanted a six-syllable Tibetan Buddhist mantra a billion times while the volunteers completed the mission between 3 a.m. and noon. About two hours later, the focus shifted to Chorten Number 76, which the King dedicated to Mr. Modi "as an enduring symbol" of his "profound appreciation" for the latter's "unwavering commitment and India's steadfast support for the realisation" of GMC. Bhutanese officials said the number was chosen because Mr. Modi turned 76 more than a month ago.

Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju, who represented India for 'Project 108', thanked the King. "This remarkable milestone is an enduring symbol of the deep spiritual and civilisational bonds between our two nations," he said, congratulating Bhutan on the achievement.

Collective spirit

Each 15 metres tall and 108 metres apart, the Jangchub Chortens, or Buddhist stupas, stand in a single meandering file along the Mau Chhu River, Gelephu's lifeline.

Addressing the people after the completion of Project 108, King Wangchuk said: "People from every walk of life and every generation came together to make this possible," stressing the Bhutanese collective spirit and ability to achieve "anything impossible".

YouTube Homework

- **Hydro Power Projects in Bhutan & Nepal**

महत्वपूर्ण तथ्य

- गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी (GMC) प्रोजेक्ट भूटान का अब तक का सबसे बड़ा और अनोखा प्रोजेक्ट है, जिसे आर्थिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण और अध्यात्म (Spiritualism) को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।

1. यह प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ?

- इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक और औपचारिक घोषणा 17 दिसंबर 2023 को भूटान के राष्ट्रीय दिवस (National Day) के अवसर पर वहां के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने की थी।
- इसके बाद, साल 2024 और 2025 के दौरान इसके मास्टर प्लान, कानूनी नियमों (Special Administrative Region Status) और भारत के साथ कनेक्टिविटी समझौतों को अंतिम रूप दिया गया। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट के शुरुआती बुनियादी ढांचे (Infra) पर काम चल रहा है।

2. इस प्रोजेक्ट में क्या-क्या शामिल है? (Concept)

- यह कोई साधारण आधुनिक शहर नहीं है। यह लगभग 2,500 वर्ग किलोमीटर (जो सिंगापुर या हॉन्गकॉन्ग से भी बड़ा है) के क्षेत्र में फैली एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (SAR - Special Administrative Region) है।
- माइंडफुलनेस का सिद्धांत: शहर का लेआउट 'ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस' (GNH) और बौद्ध दर्शन पर आधारित है। यहाँ प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर पूरी तरह प्रतिबंध है।
- 11 रहने योग्य डिस्ट्रिक्ट्स (Habitable Neighborhoods): शहर को 11 अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है, जो नदियों और जंगलों से घिरे होंगे। हर हिस्सा एक अलग थीम (जैसे डिजिटल, हेल्थ, एजुकेशन) पर काम करेगा।
- पूरी तरह सस्टेनेबल: शहर 100% रिन्यूएबल (हरित) ऊर्जा पर चलेगा और यह कार्बन-निगेटिव (Zero-Carbon) होगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

YouTube Homework

Iran says new war could last longer after Trump threats

The U.S. President would not be in a position to dictate the timing or conditions of its conclusion, says Tehran; Revolutionary Guards add that there would be 'no geographic limitations' in conflict

Agence France-Presse
TEHRAN

Iran warned on Sunday that any renewed war with the United States could last longer than the previous round of fighting, after President Donald Trump said he still had to "take care" of more targets.

Diplomatic efforts to end the West Asia war have been punctuated by repeated threats from the U.S. and Israel to resume bombardments as they hold crucial elections.

"A potential future war could last longer than previous conflict, and the American President would not be in a position to dictate the timing or the conditions of its conclusion," said Army spokesperson Mohammad Akraminia, according to Iranian state television.



Committed stance: An Iranian woman holds Iran's national flag on a street in Tehran on Sunday. AFP

Mr. Akraminia's remarks followed Mr. Trump's suggestion that the U.S. could swiftly strike its remaining targets in Iran.

"We still have to take care of, I would say one or two sites, but we can do that in 10 minutes," Mr. Trump told presspersons at his Florida residence.

Top military and political officials in Iran have warned against any new attack.

Revolutionary Guards spokesman Hossein Mohebbi on Sunday echoed a warning issued a day earlier in a written message by Iran's new Supreme Leader, Ayatollah Mojtaba Khamenei.

"In a conflict with America, there are no geographical limitations; a vast theatre has been defined for inflicting damage upon the enemy," Mr. Mohebbi said, according to state television.

महत्वपूर्ण तथ्य

YouTube Homework

Sindhu, Lakshya make it a double delight for India

The former adds the Hylo Open to the Japan Open triumph earlier in the year and boosts her hopes of making the World Tour Finals while the latter ends his title drought in style

BADMINTON

Press Trust of India
SAARBRUCKEN

Double Olympic medallist P.V. Sindhu and Lakshya Sen made it a double delight for India, claiming the women's and men's singles titles with straight-game victories in the finals of the Hylo Open Super 500 badminton tournament here on Sunday.



Super Sunday: Sindhu and Lakshya rise to the occasion when it mattered most. BWF/@BWFWORLD_OPEN

Precision and control

Former World champion Sindhu, who won the Japan Open in July and finished runner-up at the French Open last week, displayed excellent control and precision in her stroke-play to register a commanding 21-12, 21-14 win over eighth seed and world No. 25 Line Hojmark Kjaersfeldt of Denmark in a final which lasted 39 minutes.

Later, Lakshya outwitted Jonatan Christie of Indonesia 21-17, 21-10.

"It was important for me to give my 100% irrespective of who the opponent was. We've played a lot of times and for me it was important that I focus on every point. It's just not about the whole game, but every point mattered to me. I took the lead from the beginning and didn't give her a chance," Sindhu said.

With the win, the World No. 8 Sindhu earned 9,200 ranking points to strengthen her bid for a place in the season-ending World Tour Finals.

"This gives me a lot of boost, a lot of confidence. I'm happy that things are going according to plan. I'm very grateful and thankful to my whole team. Everyone has worked really hard.

"I know there were days when you're absolutely low, but still your team is there to pump you up. It's been an amazing week and I think it's time to go back and celebrate now. It has been an amazing two weeks," she said.

Lakshya, who won the Australian Open and reached the finals at Hong Kong Open in 2025, came into the final with a 3-4 head-to-head record against Christie. He made a strong start and remained in control.

"It has been quite some time since I won a tournament, so it feels good. Couple of first-round losses affect you but the way I played here gave me a lot of confidence," he said.

→ Hylo open Super 500 badminton C'ship
&
→ Japan open

महत्वपूर्ण तथ्य

Indian men and women reign supreme in Commonwealth kabaddi c'ships



Dominant display: The victorious Indian teams with their big prize. VIJAY SONEJI

Sports Bureau

Indian men and women dominated the inaugural Commonwealth kabaddi championship, winning the titles in one-sided finals at the Veer Savarkar Sports Complex in Ahmedabad on Saturday.

In the women's category, India defeated Uganda 35-15 thanks to an emphatic performance by Sakshi (nine points), Anu Sen (six points) and captain Nidhi Sharma (five points). The home team's defence was just as solid, with Ritu Mitharwal and Suman Sahu getting four tackle points each.

In the men's category, India beat Sri Lanka 54-20. Aditya Shinde led from the front with a Super 10 (10 points) from 14 raids, and was ably supported by Bharat Hooda (eight raid points).

On the defensive front, Yogesh Dahiya starred with five tackle points.

YouTube Homework

- ~~Hydro Power Projects in Bhutan & Nepal~~

महत्वपूर्ण तथ्य

- कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन इतिहास में पहली बार (Inaugural Edition) किया गया है। यह एक ऐतिहासिक और नया टूर्नामेंट है जिसे भविष्य में मुख्य राष्ट्रमंडल खेलों (Commonwealth Games) में कबड्डी को शामिल कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
- यह टूर्नामेंट 23 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक खेला गया और इसमें भारत ने इतिहास रचते हुए पुरुष और महिला दोनों वर्गों में गोल्ड मेडल (खिताब) अपने नाम कर लिया है।

कहाँ और कैसे आयोजित हुआ?

- स्थान (Venue): यह पूरा टूर्नामेंट भारत के गुजरात राज्य में अहमदाबाद के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था।
- भाग लेने वाले देश: इसमें कुल 13 राष्ट्रमंडल देशों की टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, युगांडा, केन्या, मलेशिया, इंग्लैंड, नाइजीरिया, तंजानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड और सिंगापुर शामिल थे।
- फ़ॉर्मेट (Format): इस टूर्नामेंट में कुल 23 टीमें (13 पुरुष टीमें और 10 महिला टीमें) शामिल थीं। पहले राउंड-रॉबिन पूल (ग्रुप) स्टेज के मैच हुए, जिसके बाद 30 अक्टूबर को सेमीफाइनल और 31 अक्टूबर को फाइनल मुकाबले खेले गए।

चैंपियनशिप के परिणाम (Final Results)

- भारत ने अपने घरेलू मैदान पर शानदार दबदबा दिखाते हुए बिना एक भी मैच हारे दोनों ट्रॉफियां जीतीं:
- पुरुष टीम (Men's Team): भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 54-20 से हराकर पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत की ओर से आदित्य शिंदे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 'Super 10' लगाया।
- महिला टीम (Women's Team): भारतीय महिला टीम ने फाइनल मुकाबले में युगांडा को 35-15 से मात देकर खिताब अपने नाम किया। भारत की स्टार रेडर साक्षी ने फाइनल में सबसे ज्यादा 9 पॉइंट्स स्कोर किए।
- इस टूर्नामेंट को भारत में Star Sports Network टीवी चैनलों और JioHotstar ऐप पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया था।

महत्वपूर्ण तथ्य

रक्षा मंत्रालय

Azadi Ka Amrit Mahotsav

भारतीय नौसेना के पोत त्रिशूल का ग्रीस की सूडा खाड़ी में प्रवास

प्रविष्टि तिथि: 01 NOV 2026 10:30AM by PIB Delhi

भारतीय नौसेना का पोत त्रिशूल भूमध्य सागर में अपनी तैनाती के तहत 31 अक्टूबर, 2026 को ग्रीस की सूडा खाड़ी पहुंच गया है।

पोत का चालक दल बंदरगाह पर अपने ठहराव के दौरान भारतीय नौसेना व यूनानी नौसेना के बीच समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों में भाग लेगा। इनमें एथेंस में यूनानी नौसेना और भारतीय दूतावास के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें, पेशेवर बातचीत, एक-दूसरे के जहाजों का दौरा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा, चालक दल को नेवल सपोर्ट एक्टिविटी (एनएसए) सूडा के और नटो मैरीटाइम इंटरडिक्शन ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेंटर (एनएमआईओटीसी) की सुविधाओं से भी परिचित कराया जाएगा।

भारतीय नौसेना के पोत त्रिशूल का चालक दल सूडा के युद्ध स्मारक कब्रिस्तान में श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। बंदरगाह पर इसके ठहराव के दौरान यह पोत आगंतुकों के लिए भी खुला रहेगा।

यह यात्रा समुद्री सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने के साथ-साथ भारतीय नौसेना तथा यूनान की नौसेना के बीच पेशेवर संबंधों को भी मजबूत करेगी।



महत्वपूर्ण तथ्य

प्रधानमंत्री कार्यालय

Azadi Ka Amrit Mahotsav

प्रधानमंत्री 2 नवंबर को 'भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन एवं एक्सपो 2026' का उद्घाटन करेंगे

इस शिखर सम्मेलन की थीम है – 'निवेश करें, नवाचार करें, प्रेरित करें'

इस शिखर सम्मेलन में 130 से अधिक देशों, 9 भागीदार देशों और 40 मंत्रियों की भागीदारी होगी

13 राज्य एवं केन्द्र-शासित प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी संभावनाओं और निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करेंगे

प्रविष्टि तिथि: 01 NOV 2026 5:43PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 2 नवंबर को शाम लगभग 4:30 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में 'भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन एवं एक्सपो 2026' का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे।

यह चार-दिवसीय शिखर सम्मेलन 2 से 5 नवंबर 2026 के दौरान आयोजित किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन की थीम 'निवेश करें, नवाचार करें, प्रेरित करें' है।

भारत आरई 2026 में 130 से अधिक देशों के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इनमें 40 से अधिक मंत्री, नीति-निर्माता, निवेशक, वित्तीय संस्थान और उद्योग जगत के प्रमुख शामिल हैं। यह सम्मेलन स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश, उद्योग जगत की भागीदारी और तकनीकी साझेदारियों के एक वैश्विक मंच के रूप में काम करेगा। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम इसमें भागीदार देश के तौर पर भाग लेंगे।

तेरह राज्य एवं केन्द्र-शासित प्रदेश - आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल - नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी संभावनाओं, निवेश के अवसरों और मैन्यूफैक्चरिंग संबंधी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे।

यह शिखर सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) असेंबली के 9वें सत्र और हरित हाइड्रोजन पर चौथे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीजीएच) के साथ आयोजित किया जाएगा। जहां 'भारत आरई' स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश, उद्योग और तकनीकी साझेदारियों पर ध्यान केन्द्रित करेगा, वहीं आईएसए असेंबली सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाएगी और इसमें वित्त एवं संस्थागत क्षमता जैसे पहलू शामिल होंगे। आईसीजीएच का मुख्य फोकस हरित हाइड्रोजन से जुड़ी तकनीकों, निवेश और विस्तार पर होगा। ये तीनों मंच मिलकर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करेंगे और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने की प्रक्रिया में तेजी लाएंगे।

महत्वपूर्ण तथ्य

रक्षा मंत्रालय

Azadi Ka Amrit Mahotsav

एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने भारतीय वायुसेना के 29वें प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया; वायुसेना के भविष्य के लिए 'वायु' को मार्गदर्शक दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत किया

प्रविष्टि तिथि: 01 NOV 2026 5:18PM by PIB Delhi

एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएम, बीएसएम ने 1 नवंबर को भारतीय वायुसेना के 29वें प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने राष्ट्रीय समर स्मारक पर देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद, नई दिल्ली स्थित वायुसेना स्टेशन पर उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

एयर चीफ मार्शल दीक्षित को एक परीक्षण पायलट और योग्य उड़ान प्रशिक्षक के रूप में 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण परिचालन और रणनीतिक पदों पर कार्य किया है। इनमें मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ में प्रमुखों की स्टाफ समिति के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख (सीआईएससी), केंद्रीय वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ और वायुसेना के उप प्रमुख जैसे पद शामिल हैं।

वायुसेना प्रमुख ने अपने पहले संबोधन में भारतीय वायुसेना के लिए अपना दृष्टिकोण और प्राथमिकताएं स्पष्ट कीं। उन्होंने 'वायु' नाम से एक मार्गदर्शक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसके चार प्रमुख स्तंभ भारतीय वायुसेना की भविष्य की दिशा तय करेंगे।

V – सतर्कता, विजय एवं तत्परता: सभी वायुसेना इकाइयों में परिचालन तैयारियों का उच्चतम स्तर बनाए रखना और युद्ध क्षमता को निर्धारित मानकों के अनुरूप बहाल करना।

A – आत्मनिर्भरता: विमान, संवेदक, हथियार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य परिचालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना तथा निरंतर युद्ध क्षमता बनाए रखना है।

Y – युक्ति: युद्ध सिद्धांतों, प्रौद्योगिकी और परिचालन प्रक्रियाओं में दूरदर्शिता व नवाचार को अपनाना। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कमान एवं नियंत्रण प्रणाली, ड्रोन रोधी क्षमताएं, परिचालन में लचीलापन व उभरते हुए युद्ध क्षेत्र शामिल हैं।

U – प्रयासों में एकजुटता: राष्ट्रीय दृष्टिकोण 'जय' यानी संयुक्तता, आत्मनिर्भरता एवं नवाचार के अनुरूप थलसेना, नौसेना और विभिन्न राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय व संयुक्त कार्यक्षमता को और मजबूत करना।

Home Assignment

- World Radio Day
- PM-Poshan Scheme

Thanks For Watching

Follow us for more Updates

@RRESULTMITRAOFFICIAL

Join our Telegram

@SUNILVERMA_THEIASMENTOR

Follow on Instagram

Subscribe Now

Stay Connected



